वर्ष 12 • अंक 273 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 3 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 3

अभी नहीं बदलेगी मझोले एवं छोटे शेयरों की किस्मत

धर्मेंद्र प्रधान ▶▶ पृष्ठ 4

ओएएलपी के चौथे दौर में ओएनजीसी को सभी ब्लॉक

डॉलर रु. 71.40 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 79.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु 39058 ▲ 96 रुपये | सेंसेक्स 41626.60 ▲ 320.26 | निफ्टी 12282.20 ▲ 99.77 | निफ्टी फ्यूचर्स 12339.30 ▲ 57.10 | ब्रेंट क्रूड 66.60 डॉलर ▲ 0.30 डॉलर

एक नज़र

विनिर्माण गतिविधियां 7 महीने के उच्चतम स्तर पर

देश में विनिर्माण गतिविधियां दिसंबर में पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। निक्कई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेज मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) दिसंबर में 52.7 के स्तर पर पहुंच गया। नवंबर में यह 51.2 के स्तर पर रहा था। 50 से अधिक का स्तर तेजी और इससे नीचे का स्तर संकुचन दर्शाता है। अक्टूबर में पीएमआई 50.6 के स्तर पर रहा, जो दो वर्षों का सबसे निचला स्थर था। विनिर्माण में तेजी के बावजूद कारोबारी उम्मीद तीन वर्ष के निचले स्तर पर आ गई। पृष्ठ 4

भारत बॉन्ड ईटीएफ का बाजार में आगाज

भारत बॉन्ड ईटीएफ गुरुवार को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध हो गया। यह ईटीएफ 12 दिसंबर को खरीदारी के लिए खुला था और दो चरणों में इसकी पेशकश की गई थी। तीन वर्ष की श्रेणी के लिए 6,982 करोड़ रुपये के आवेदन आए थे, जबकि 10 वर्ष की श्रेणी के लिए 5,413 करोड़ रुपये की बोलियां आई थीं। करीब 55,000 आवेदनों के साथ नई फंड पेशकश में खुदरा कारोबारियों ने जमकर भागीदारी की।

इस्पात कंपनियों ने 1,500 रु. प्रति टन तक बढ़ाए दाम

घरेलू इस्पात उत्पादकों ने जनवरी के लिए अपने उत्पादों के दाम 1,000 से 1,500 रुपये प्रति टन तक बढ़ाने की घोषणा की है। बढ़ती लागत और इन उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का निर्णय लिया। जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेएसपीएल) के प्रबंध निदेशक वी आर शर्मा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि लौह अयस्क खनिकों ने दाम 600 रुपये प्रति टन बढ़ा दिए हैं, जिससे इस्पात उत्पादन की लागत 1,000 रुपये प्रति टन बढ़ गई है। जनवरी लगातार चौथा ऐसा महीना है, जब घरेलू इस्पात कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। पृष्ठ 6

प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा बने एनएमसी के पहले प्रमुख

दिल्ली स्थित एम्स के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। एनएमसी देश में चिकित्सा शिक्षा नियामक के तौर पर भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का स्थान लेगा। कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह तीन साल की अवधि या 70 साल की उम्र तक इस पद पर रहेंगे। एमसीआई के संचालन मंडल में महासचिव राकेश कुमार वत्स को एनएमसी का सचिव बनाया गया है।

अधिक चैनल बन सकते हैं फ्री-टू-एयर

प्रसारण कंपनियां कुछ और चैनल नि:शुल्क श्रेणी में डाल सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार ये ऐसे चैनल हैं, जो अधिक लोकप्रिय नहीं है। प्रसारण कंपनियां इन्हें 200 चैनलों वाले पैक का हिस्सा बना सकती हैं, जो 130 रुपये शुल्क पर उपलब्ध होंगे। प्रसारण कंपनियों सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और इंडिया पर अधिक असर पड़ सकता हैं क्योंकि वे अपने पैक पर 35 से 54 प्रतिशत तक छूट दे रही हैं। प्रसारकों ने अपने चैनलों की संशोधित कीमत तय करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक स्टार इंडिया के गुरुवार को अपना नया चैनल पैक पेश करने की संभावना थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है।

व्यापार गोष्ठी

नए साल से आर्थिक एवं कारोबारी उम्मीदें ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या अगले वित्त वर्ष में सुधर जाएगा एफएमसीजी कंपनियों का कारोबार ?

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या नई परियोजनाओं में तेजी है अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत	
हां	55.56%
नहीं	44.44%

उच्चतम न्यायालय पहुंची टाटा

एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई

देव चटर्जी
मुंबई, 2 जनवरी

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ आज उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। पंचाट ने साथ ही समूह के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। उच्चतम न्यायालय अगले सप्ताह टाटा की याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

टाटा संस ने अपनी याचिका में कहा है कि मिस्त्री की निवेश कंपनियों ने भी चंद्रशेखर को हटाने की मांग नहीं की थी और फिर भी एनसीएलएटी ने उनकी नियुक्त को अवैध करार दिया। इससे समूह का कामकाज प्रभावित हुआ है। एनसीएलएटी के मुताबिक टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा और एन के पूनावाला टाटा संस और समूह की अन्य कंपनियों में बेजा हस्तक्षेप करते थे। इस बारे में टाटा ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके न्यासियों की भूमिका के बारे में पंचाट की टिप्पणी बेबुनियाद और तथ्यों से परे है।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 में टाटा संस के बोर्ड ने मिस्त्री को अक्षम करार देते हुए कार्यकारी चेयरमैन के पद से बर्खास्त कर दिया था। मिस्त्री परिवार की निवेश कंपनियों की टाटा संस में 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया। अपीलीय पंचाट ने 18 दिसंबर के अपने फैसले में टाटा संस को मिस्त्री को कार्यकारी चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया।

टाटा संस ने उच्चतम न्यायालय से उसकी याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि एनसीएलएटी के आदेश को खारिज करने की जरूरत है क्योंकि टाटा संस के निदेशक के तौर पर मिस्त्री की कारगुजारियों से टाटा संस बोर्ड की निष्ठा और हितों को खतरा पैदा हो गया था। टाटा संस ने कहा कि टाटा समूह से हटाए जाने के बाद मिस्त्री ने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे टाटा समूह के हितों को नुकसान पहुंचा। मिस्त्री द्वारा टाटा संस के निदेशक मंडल को भेजे गए गोपनीय ईमेल को जानबूझकर लीक किया गया और मिस्त्री की पहल पर बोर्ड बैठक के गोपनीय ब्योरे को सार्वजनिक किया गया। साथ ही मिस्त्री ने अवैध तरीके से आय कर अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया और टाटा संस के दस्तावेज उन्हें सौंपे। ■ पृष्ठ 3

टाटा संस की दलीलें

- मिस्त्री को बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि इससे टाटा समूह का कामकाज गड़बड़ा जाएगा
- एन चंद्रशेखरन की अगुआई में टाटा संस के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है
- चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध करार देने का पंचाट का फैसला तर्कसंगत नहीं है

- मिस्त्री की कंपनियों ने उन्हें टाटा समूह की तीन कंपनियों में निदेशक के तौर पर बहाल करने का अनुरोध नहीं किया था। इसलिए एनसीएलएटी ने उन्हें बेबुनियाद राहत दी है।
- मिस्त्री ने एकतरफा अंदाज में और अवैध तरीके से आय कर अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया था और उन्हें दस्तावेज सौंपे थे

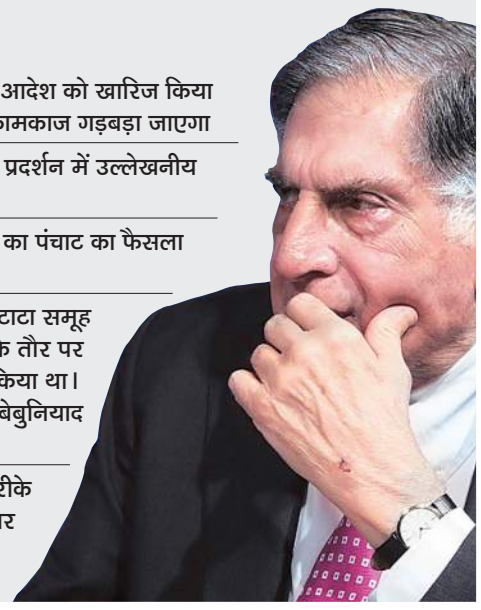

आरओसी पर संशोधन को तैयार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय पंचाट (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को कहा कि वह कंपनी पंजीयक (आरओसी), मुंबई के खिलाफ दिए अपने आदेश से संबंधित बाध्यताएं दूर करने को तैयार है। पंचाट के आदेश में कहा गया था कि टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में तब्दील किया जाना अवैध था और इसमें आरओसी को इसे पलटने का निर्देश दिया गया था। ■ पृष्ठ 3

विनिवेश लक्ष्य से काफी पीछे!

बीएस संवाददाता
मुंबई, 2 जनवरी

सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपये से काफी पीछे रह सकती है। इसकी वजह यह है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) और एयर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया मार्च अंत तक पूरी होती नहीं दिख रही है। इस सूरत में सरकार विनिवेश लक्ष्य से 65,000 करोड़ रुपये से अधिक के अंतर से पीछे रह सकती है।

इस बारे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'सरकार को संभावित बोलीदाताओं की शर्तों पर ध्यान देना होगा। कभी-कभी वे सौदा करने से पहले पूरी तरह सोच-विचार करना चाहते हैं।' यह आशंका ऐसे समय में उभरी है जब सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बजट अनुमान का 115 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अगर राजस्व संग्रह में तेज वृद्धि नहीं हुई या चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में विनिवेश योजनाएं पटरी पर नहीं लौटीं तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सरकार के हाथ से फिसल सकता है।

वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक सरकार विनिवेश से 17,364 करोड़ रुपये जुटाने में ही सफल रही है और विनिवेश लक्ष्य का 84 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना अभी शेष है।

सरकार बीपीसीएल में अपना 53.3 प्रतिशत हिस्सा एक रणनीतिक निवेशक को बेचना चाहती है। इससे गुरुवार के भाव के अनुसार सरकार को 56,480 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस बीच, गुरुवार के ही भाव के आधार पर कॉनकॉप में सरकार की 31 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 10,724 करोड़ रुपये आंका गया है। इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 67,204 करोड़ रुपये या इससे भी अधिक रकम प्राप्त हो सकती है। इनमें अगर एयर इंडिया में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री भी शामिल कर ली जाए तो कुल रकम 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। क्रेडिट सुइसे के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति में एयर इंडिया की बिक्री से सरकार को 18,000 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। हालांकि निवेश बैंकरों का कहना है कि विमनन कंपनी की बिक्री से हासिल रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि इस पूरे सौदे का ढांचा इसकी शर्तें क्या होती हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी को 8,556 करोड़ रुपये (अस्थायी अनुमान) नुकसान हुआ था। एयर इंडिया पर करीब 30,000 करोड़ रुपये कर्ज है। इस वर्ष अब तक सरकार अपनी हिस्सदेारी बेचने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेट फंडों पर खासी निर्भर रही है। सरकार को चालू वित्त वर्ष में सीपीएसई ईटीएफ के फॉलो-ऑन ऑफर से 10,000 करोड़ रुपये और भारत 22 ईटीएफ के दूसरे फॉलो-ऑन-ऑफर से 4,368 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले वर्ष नवंबर में सरकार ने कॉनकॉर में 31 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के साथ बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी थी। एससीआई में सरकार की 64 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री का मूल्य गुरुवार को बंद बाजार भाव के आधार पर 1,772 करोड़ रुपये आंका गया है।

प्रस्तावित विनिवेश

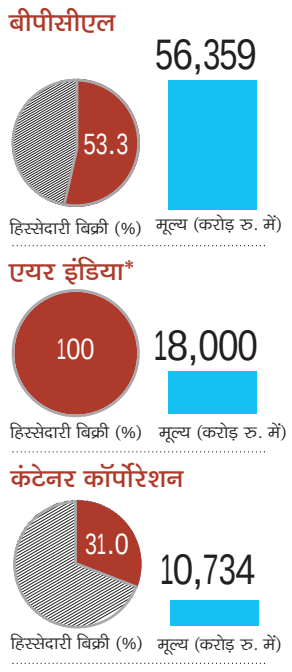

नोटः मूल्यांकन शुक्रवार के बाजार भाव पर आधारित हैं
* क्रेडिट सुइस का अनुमान

एफएमसीजी को कमजोर खुराक

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 2 जनवरी

एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनी मैरिको ने कहा कि चालू वित्त वर्ष तीसरी तिमाही में खपत उम्मीदों के अनुसार नही रही। कंपनी ने बुधवार को कहा कि तीसरी तिमाही में मांग सुधरने का संकेत नहीं मिला। कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को लिखे पत्र में कहा, 'कंपनी के पर्सनल केयर खंड में वृद्धि दर कमजोर रही, जबकि खाद्य एवं सहायक श्रेणियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।' 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कारोबारी प्रदर्शन कर रिपोर्ट बीएसई को भेजने के बाद कंपनी का शेयर 2.43 प्रतिशत फिसल कर 337.45 रुपये पर बंद हुआ। मैरिको ने कहा कि नारियल एवं केश तेल जैसे उत्पादों का प्रदर्शन कमजोर रहने से तीसरी तिमाही के दौरान घरेलू बिक्री प्रभावित हुई। कंपनी ने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि लोग फिलहाल इन उत्पादों की खरीदारी को तरजीह नहीं दे रहे हैं।

इसी खंड की एक दूसरी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने भी दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा के समय हालात चुनौतीपूर्ण बताया था। एचयूएल ने यह विश्वास जरूर जताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार आवश्यक उपाय जरूर करेंगे। हालांकि कंपनी ने कहा कि निकट अवधि में मांग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुस्त लग रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कारोबार करने वाली इमामी ने कहा कि निकट अवधि में मांग सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इमामी लिमिटेड में निदेशक मोहन गोयनका ने कहा, 'मॉनसून अच्छा रहने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में मांग नहीं सुधरी है। हालांकि धीरे-धीरे स्थिति में सुधार जरूर दिख रहा है और अगले 2 से 3 तिमाहियों में मांग में तेजी दिखनी चाहिए।'

इमामी की कुल सालाना बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 45 से 50 प्रतिशत रहता है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का कहना है कि 2018-19 में दर्ज 5 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में यह रफ्तार मात्र 2 प्रतिशत रह सकती है। एजेंसी के अनुसार सितबर 2020 के अंत कारोबार पटरी पर आ सकता है। इसका मानना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में व्यक्गित आय कर में कमी से उपभोक्ताओं का उत्साह बढ़ सकता है, जिससे वे उपभोग पर अधिक व्यय करने की स्थिति में होंगे। कारोबार की पहुंच बढ़ाने और वितरण तंत्र मजबूत करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में दूर-दूर तक कारोबार पहुंचाने से भी एफएमसीजी कंपनियों की हालत सुधर सकती है। एडिलवाइस सिक्योरिटीज में कार्यकारी उपाध्यक्ष, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, अवनीश रॉय ने कहा, 'मॉनूसन में अच्छी बारिश और सरकारी उपायों की झलक एफएमसीजी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजों में नहीं मिल सकती है।'

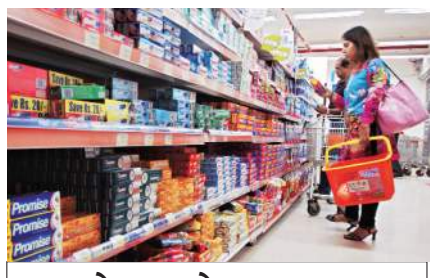

कमजोर कारोबार

कंपनी	2019-20 पहली छमाही	2018-19 दूसरी छमाही	वृद्धि दर (% में)
एचयूएल	20,128	18,979	6
मैरिको	3,995	3,864	3
आईटीसी	25,525	24,066	6
इमामी	1,310	1,143	5

स्रोतः कंपनियां सभी आंकड़े करोड़ रुपये में

दिल्ली: जीएसटी वसूली 12 फीसदी बढ़ी, लक्ष्य अधूरा

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 2 जनवरी

- दिसंबर,2019 में 1,760 करोड़ रुपये जीएसटी वसूली, वर्ष 2018 के दिसंबर में हुई थी 1,570 करोड़ रुपये
- दिसंबर में जीएसटी वसूली में वृद्धि के बावजूद लक्ष्य अधूरा

दिल्ली सरकार को दिसंबर में जीएसटी संग्रह के मोर्चे पर राहत मिली है। दिसंबर में जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है। नवंबर 2019 में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि दिसंबर में सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में तेजी के बावजूद लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

दिल्ली जीएसटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार का जीएसटी संग्रह कुल 1,760 करोड़ रुपये रहा, जिनमें 1,030 करोड़ रुपये एसजीएसटी और 730 करोड़ रुपये आईजीएसटी शामिल हैं। दिसंबर 2018 में 1,570 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। अधिकारी ने दिसंबर में जीएसटी में 18 प्रतिशत वृद्धि पर संतुष्टि जताई। अधिकारी ने कहा कि दिसंबर में अच्छी वृद्धि के मद्देनजर वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अब जीएसटी वसूली में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार के जीएसटी वसूली में दिसंबर में 12 फीसदी वृद्धि दर समान अवधि में केंद्र के जीएसटी में 9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अधिक है। अधिकारी ने कहा कि कर चोरी रोकने और राजस्व वृद्धि के लिए किए सख्य उपायों के सकारात्मक असर दिख रहे हैं।

हालांकि जीएसटी संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली के लिए जीएसटी संग्रह का मासिक लक्ष्य 2,372 करोड़ रुपये है, लेकिन कुल संग्रह 1,760 करोड़ रुपये ही रहा। इस तरह, जीएसटी संग्रह लक्ष्य का करीब 75 प्रतिशत ही रहा।

कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा फास्टैग

अमृता पिल्लै
मुंबई, 2 जनवरी

नवी मुंबई के वाशी ब्रिज में टोल संग्रह करने वालों के लिए फास्टैग और इसके क्रियान्वयन से जुड़े सवालों का सामना करना अब रोज की बात हो गई है। कुछ का कहना है कि वे इसकी समयसीमा को लेकर निश्चित नहीं हैं। देशभर में टोल प्लाजा पर तैनात हजारों कर्मचारियों का भविष्य भी अधर में लटक रहा है।

अभी केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही फास्टैग की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। वाशी ब्रिज का परिचालन महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) करता है। फास्टैग को अभी भले ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जा रहा है लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इससे लोगों की नौकरी जाएगी या नहीं।

गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक केके मोहंती ने कहा, 'अब तक किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई है। वे इस व्यवस्था में मदद कर रहे हैं और दूसरी समस्याओं को देख रहे हैं।' फास्टैग की व्यवस्था को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इसमें आरएफआईडी तकनीक के जरिये टोल संग्रह किया जाता है। इससे ईंधन और समय की बचत होगी तथा यातायात निर्बाध रूप से चलेगा। चूंकि इसमें नकद संग्रह में कमी आएगी, इसलिए इसमें कर्मचारियों की संख्या में भी कमी आ सकती है। मोहंती ने कहा कि फास्टैग से टोल कर्मचारियों की संख्या में 10 से 15 फीसदी की कमी हो सकती है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 570 टोल प्लाजा अभी परिचालन में हैं। इनमें कुछ कितने कर्मचारी हैं, इसकी कोई निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। उद्योग से जानकारों के मुताबिक चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की संख्या 100 से 125 होती है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर कुशल सिंह ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि इससे रोजगार का नुकसान होगा लेकिन काम का स्वरूप बदल जाएगा। कंपनियां उन्हें दूसरी जगह लगा सकती हैं।' अलबत्ता, टोल प्लाजा पर काम कर रहे अधिकांश कर्मचारी आगे शायद ही स्थायी कर्मचारी होंगे। मोहंती ने कहा कि सुपरवाइजरी स्टाफ कंपनी के कर्मचारी रहेगे लेकिन बाकी ठेके वाले कर्मचारी होंगे। उन्होंने कहा, 'कंपनियों को अपनी जरूरतों के हिसाब से उनके अनुबंधों में बदलाव करना होगा।'

राजमार्गों पर टोल

खबरों में रहे स्टॉक

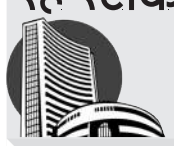

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

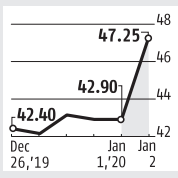

दिसंबर में बिक्री 47 फीसदी बढ़कर 16.8 लाख टन रही

₹ 42.90 पिछला बंद भाव
₹ 47.25 आज का बंद भाव
▲ 10.14 %

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज

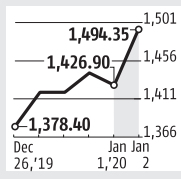

आईआरडीए ने अपोलो म्युनिख हेल्थ इंश्यो. का हिस्सा बेचने को दी मंजूरी

₹ 1,426.90 पिछला बंद भाव
₹ 1,494.35 आज का बंद भाव
▲ 4.73 %

अल्ट्राटेक सीमेंट

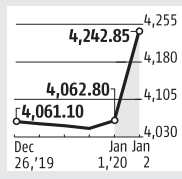

मांग में इजाफे के अनुमान से सीमेंट शेयरों में तेजी

₹ 4,062.80 पिछला बंद भाव
₹ 4,242.85 आज का बंद भाव
▲ 4.43 %

टाटा मोटर्स

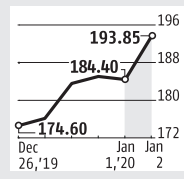

दिसंबर में देसी बिक्री में 16 फीसदी की उछाल

₹ 184.40 पिछला बंद भाव
₹ 193.85 आज का बंद भाव
▲ 5.12 %

मैरिको

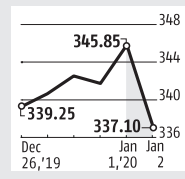

तीसरी तिमाही में भारतीय कारोबार में मामूली गिरावट

₹ 345.85 पिछला बंद भाव
₹ 337.10 आज का बंद भाव
▼ 2.53 %

संक्षेप में

अनिल अग्रवाल के पिता का निधन

खनन क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल का निधन हो गया है। वह 87 वर्ष के थे। वेदांत रिसोर्सेज के कार्यकारी चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। अग्रवाल ने ट्वीट किया, 'अपने प्रिय पिता श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल के निधन से मैं बहुत आहत और दुखी हूं। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।' अग्रवाल ने धातु के कबाड़ कारोबार से शुरुआत की थी। वह पटना में पले बढ़े। वहां उनके पिता शुरुआती वर्षों में एल्युमीनियम कंडक्टर बनाया करते थे। पिछले तीन दशक से द्वारका प्रसाद अग्रवाल वेदांत समूह की परमार्थ इकाई वेदांता फाउंडेशन से जुड़े थे। उनका निधन गुरुवार को मुंबई में हुआ। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा। *भाषा*

इंटरपोल ने लेबनान को भेजा नोटिस

इंटरपोल ने भगोड़े कारोबारी कार्लोस गोन की गिरफ्तारी के लिये लेबनान के न्याय विभाग को रेड कॉर्नर नोटिस भेजा है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। नेशनल न्यूज एजेंसी ने न्याय मंत्री अलबर्ट सारहन के हवाले से कहा कि सार्वजनिक अभियोजक को कार्लोस गोन मामले में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस मिला है। उल्लेखनीय है कि घोसन को वित्तीय अनियमितता के मामलों में जापान में घर में नजरबंद करके रखा गया था। *एजेंसी*

भारत में 5जी पर दांव लगाने को तैयार क्वालकॉम

रोमिता मजूमदार
मुंबई, 2 जनवरी

5जी पेशकश का लाभ उठाने की कवायद

- अगली दो तिमाहियों में 5जी फोन पेश किए जाने की संभावना है
- क्वालकॉम ने 5जी और 4जी के लिए भी तैयार चिपसेट की सीरीज तैयार की है
- अमेरिका के बाद क्वालकॉम के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रतिभाओं का स्थान है
- देश में क्वॉलकॉम के लगभग 10,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं

चिपसेट निर्माता क्वालकॉम अगली दो तिमाहियों में भारतीय बाजार में 5जी-आधारित फोन की पेशकश की संभावना देख रही है। 5जी फोन में इस्तेमाल होने वाले चिपसेट की निर्माता दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सहायक नेटवर्क पेश किए जाने से पहले डिजिटल उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्वालकॉम इंडिया एवं सार्क के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष राजन वागडिया का कहना है कि चिप निर्माता देश में भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ 5जी पेशकश में तेजी को लेकर आश्वस्त है।

वागडिया ने कहा, 'हम इस तिमाही के शुरू में या अगली तिमाही में भारत में किफायती 5जी फोन की पेशकश की उम्मीद कर रहे हैं। लोग अब स्मार्टफोन में दीर्घावधि निवेश की संभावना तलाश रहे हैं और इनकी पेशकश के बाद वे इनका इस्तेमाल करेंगे। जहां 4जी बरकरार रहेगी, वहीं 5जी भी इसके साथ पेश होगी।'

क्वालकॉम ने 5जी और 4जी के लिए भी तैयार चिपसेट की सीरीज तैयार की है। उपकरण प्रदाताओं का कहना है कि दूरसंचार ऑपरेटर आखिरकार 5जी की राह में शामिल होंगे, क्योंकि यह 4जी सेवाएं मुहैया कराने की तुलना में सस्ती होगी। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने हालांकि मौजूदा समय में 5जी सेवाओं के लिए सिर्फ 3.3-3.6 गीगाहट्र्ज रेंज में मिड-बैंड स्पेक्ट्रम निर्धारित किया है।

क्वालकॉम ने हाल में घोषणा की कि वह भारत में 5जी यूज केस विकसित करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम, फ्लिपकार्ट और एमेजॉन इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है। वागडिया ने कहा, 'हमने जियो के साथ कार्य कर और अपनी वैश्विक दक्षता का इस्तेमाल कर 4जी एलटीई के केस तैयार करने में योगदान दिया। ऐसा ही 5जी के लिए होगा।' वागडिया ने कहा कि ऑपरेटरों को मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम (एमएम-वेव) पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो खासकर उद्यमों के लिए इस्तेमाल के साथ भारत में इस उद्देश्य के लिए बेहद जरूरी होगा।

देश में क्वालकॉम के लगभग 10,000 इंजीनियर काम करते हैं। कंपनी ने तीन चिपसेट पेश किए हैं जिनमें स्नैपड्रैगन 865 5जी, स्नैपड्रैगन 75 5जी और स्नैपड्रैगन 765जी 5जी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जहां 2जी, 3जी या 4जी जैसी पिछली पीढ़ी की सेल्युलर नेटवर्क प्रौद्योगिकियों पर अमल अन्य देशों की तुलना में काफी बाद में हुआ, जिसके विपरीत, 5जी को लेकर चर्चाएं लगभग एक साथ हो रही हैं। उन्होंने कहा, 'पिछली जेनरेशन के विपरीत, 5जी की पेशकश 4जी के साथ साथ की जा सकती है और इसमें समान इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। यह एक समर्पित 5जी नेटवर्क पर आधारित पेशकश होगी, जबकि 4जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अभी भी डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग (डीएसएस) जैसी प्रौद्योगिकी के साथ किया जा सकेगा।'

क्वालकॉम मौजूदा समय में कनेक्टिविटी आधारित सॉल्युशनों पर देश में कई स्टार्टअप के साथ काम कर रही है। कंपनी ने पेटेंट आवेदन और अपने स्वयं के आईपी में उनकी मदद के लिए भी इन कंपनियों के साथ भागीदारी की है।

वागडिया ने कहा कि कंपनी सॉल्युशन विकसित करने के लिए भारतीय उपकरण निर्माताओं के साथ भी मिलकर काम कर रही है। क्वालकॉम खासकर भारतीय स्टार्टअप को ध्यान में रखकर 15 करोड़ डॉलर के वेंचर फंड के लिए प्रतिबद्ध है।

स्मार्टफोन की बिक्री 2020 में 14 फीसदी बढ़ेगी

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 2 जनवरी

उपभोक्ता सामान की ज्यादातर श्रेणी में जारी मंदी के बाद भी स्मार्टफोन की बिक्री साल 2020 में दो अंकों में बढ़ेगी। एनलिस्ट फर्म टेकआर्क का अनुमान है कि चीन के बाद स्मार्टफोन के दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत में स्मार्टफोन की बिक्री 14 फीसदी तक बढ़ेगी।

शुरुआती अनुमान के मुताबिक साल 2019 में स्मार्टफोन की बिक्री 12 फीसदी बढ़कर 14.5 करोड़ रही। मौजूदा हैंडसेट्स को अपग्रेड करने पर विचार कर रहे खरीदारों को जोड़ लें तो स्मार्टफोन की बिक्री इस साल 16.5 करोड़ फोन के अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच सकता है, जो सालाना आधार पर 13.8 फीसदी ज्यादा है।

स्मार्टफोन का शिपमेंट हालांकि सुस्त रह सकता है जिसकी वजह जरूरत से ज्यादा उत्साहित वेंडर हैं जिन्होंने 2019 की दूसरी छमाही में उससे ज्यादा हैंडसेट का शिपमेंट किया, जितना वे बेच सकते थे। टेकआर्क के मुख्य विश्लेषक फैसल कावूसा के मुताबिक, रियलमी जैसी कंपनी ने त्योहारी सीजन में भारी मांग के अनुमान से सितंबर तिमाही में लाखों स्मार्टफोन का अतिरिक्त शिपमेंट किया। अनुमान बताते हैं कि साल 2019 के आखिर में कुल 70-100 लाख अतिरिक्त स्मार्टफोन इन्वेंट्री में पड़े हुए थे।

आईडीसी इंडिया के शोध निदेशक नवकेंदर सिंह ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि स्मार्टफोन के शिपमेंट में साल 2019 में हुई बढ़ोतरी के मुकाबले इस साल ज्यादा इजाफा होगा। उन्होंने कहा, साल 2019 में हम स्मार्टफोन के शिपमेंट में अधिकतम एक अंक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं और इस साल भी यह इससे शायद ही आगे निकलेगा। फीचर फोन ग्राहकों को स्मार्टफोन की ओर आकर्षित करने में बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों की नाकामी एक अहम वजह है। श्याओमी, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे बड़े ब्रांडों में से किसी ने भी शुरुआती दौर वाले मॉडल (3,000 रुपये से 5,000 रुपये) पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। स्मार्टफोन खरीदने की लागत अभी भी फीचर फोन के मुकाबले कम से कम 60 फीसदी ज्यादा है।

सालाना आधार पर वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट

अर्थव्यवस्था पर लगातार दवाब के चलते घरेलू वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट देखी गई जिसके लिए ट्रकों की मांग में कमी, सरकारी खर्च में धीमापन तथा दूसरे कारक शामिल हैं। हालांकि दिसंबर में मासिक आधार पर वाहन बिक्री 10-15 प्रतिशत बढ़ी है जिसका प्रमुख कारण वाहनों पर दी गई भारी छूट रहा।

वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने बताया कि एक साल पहले दिसंबर 2018 की 36,180 इकाइयों के मुकाबले इस बार दिसंबर 2019 में 31,469 इकाइयों की ही बिक्री हुई। हालांकि नवंबर 2019 की 27,657 इकाइयों के मुकाबले दिसंबर की बिक्री में 13.8 प्रतिशत इजाफा देखा गया। कंपनी के मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में दिसंबर 2019 के दौरान 6,957 वाहनों की बिक्री हुई जो एक साल पहले की 11,506 इकाइयों की बिक्री से 40 प्रतिशत कम है। हालांकि नवंबर 2019 की 6,050 इकाइयों के मुकाबले यह 15 प्रतिशत अधिक है। टाटा मोटर्स की वाणिज्यिक वाहन कारोबार इकाई के अध्यक्ष गिरीश वाघ कहते हैं, 'दिसंबर में खुदरा बिक्री करीब 13 प्रतिशत अधिक रही। फिलहाल हम बीएस-6 मानकों को लागू करने के करीब हैं। कुल बिक्री लगातार दूसरे माह बढ़ी है और कंपनी के मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक श्रेणी के वाहनों की बिक्री नवंबर माह के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक रही।' वाघ कहते हैं, 'वाहनों के बारे में जानकारी लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। वाहन मालिकों को इस बात का आभास है कि उनके पुराने वाहनों को बदलने का यह सही समय है।'

दोपहिया विनिर्माताओं ने निराशा के साथ की साल की समाप्ति

शैली सेठ मोहिले

पिछले महीने बिक्री में गिरावट के रुख का विस्तार करते हुए दोपहिया कंपनियों ने साल 2019 की समाप्ति निराशा के साथ की। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, रॉयल एनफील्ड और सुजूकी मोटरसाइकल समेत पांच अग्रणी विनिर्माताओं की संयुक्त बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 11.39 फीसदी घटकर 11 लाख रह गई। कंपनियों ने डीलरों को आपूर्ति पर नियंत्रण रखा ताकि मांग के हिसाब से आपूर्ति हो। भारत की वाहन कंपनियां डीलरों को भेजे वाहन बिक्री के तौर पर गिनती है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले बीएस-6 उत्सर्जन नियम से पहले कंपनियों ने नियंत्रित आपूर्ति की। अगले दो महीने में भी बिक्री नकारात्मक रह सकती है क्योंकि कंपनियां नए नियम का अनुपालन करने वाले मॉडलों पर काम कर रही है।

बिक्री के आंकड़े

कंपनियां	दिसंबर 18	दिसंबर 19	सालाना बदलाव(%)
हीरो मोटोकॉर्प	453,985	424,845	-6.41
बजाज ऑटो	157,252	124,125	-21
टीवीएस मोटर	209,906	157,244	-25
रॉयल एनफील्ड	58278	50416	-13.49
सुजूकी मोटरसाइकल	453,985	424,845	0

3डी प्रिंटिंग के लिए एचएएल और विप्रो 3डी ने मिलाया हाथ

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 2 जनवरी

हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) और विप्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग (डब्ल्यूआईएन) के धातु योगज विनिर्माण (एएम) कारोबार - 'विप्रो 3डी' ने धातु संबंधी 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए एयरोस्पेस पुर्जों के डिजाइन, विकास, निर्माण और मरम्मत के लिए हाथ मिलाया है। इस 3डी धातु प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए विकसित किए गए पुर्जों की सटीकता और प्रमाणिकता इस समझौते के अन्य प्रमुख तत्व हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि इस शुरुआत से 3डी धातु प्रिंटिंग भारतीय एयरोस्पेस की मुख्यधारा में आएगी।

विप्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के मुख्य कार्याधिकारी प्रतीक कुमार ने कहा कि विप्रो 3डी और एचएएल पहले भी एकजुट होकर काम किया है। इससे एयरोस्पेस में योगज तकनीक की अगुआई करने में हमारे सहयोगपूर्ण प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

3डी धातु प्रिंटिंग में डिजाइनिंग में तेजी से बदलाव, भार और ज्यामिति का बेहतरीन तरीके से उपयोग, प्रदर्शन में सुधार और लचीले विनिर्माण जैसे फायदे के कारण वैश्विक स्तर पर एयरोस्पेस उद्योग 3डी धातु प्रिंटिंग अपनाने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक रहा है। मार्केट्सऐंडमार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक यह बाजार 23 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 4.76 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने भी एयरो-इंजनों रखरखाव और विनिर्माण तथा विमानों के डिजाइन के क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए 3डी प्रिंटिंग के लिए बेंगलूरु में सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक जांच के लिए पुर्जों या प्रोटोटाइप मॉडल बनाने तक ही सीमित हैं।

एनडीटीवी के प्रवर्तकों की सेबी के नोटिस को चुनौती

मीडिया कंपनी एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आंतरिक व्यापार नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में वर्ष 2018 में सेबी द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि वह छह जनवरी को आदेश सुनाएगी। उसने कहा कि रॉय दंपति नोटिस का सामना कर सकते हैं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रह सकते हैं। याचिका में अदालत से मांग की गयी है कि नोटिस को रद्द किया जाए और सेबी को रॉय दंपति को सभी दस्तावेजों, रिकॉर्ड तथा आंतरिक फाइलों एवं नोटिंग्स को देखने की अनुमति दी जाए जिनके आधार पर नियामक ने नोटिस जारी किया। *भाषा*

बीएस बातचीत

अभी नहीं बदलेगी मिडकैप और स्मॉलकैप की किस्मत

साल 2019 सेंसेक्स और निफ्टी-50 के लिए भले ही अच्छा रहा हो लेकिन मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांकों को झटका लगा। इसके साथ ही इक्विटी (मुख्य बेंचमार्क सूचकांकों) से रिटर्न 2000-2009 की सालाना 13 फीसदी चक्रवृद्धि रफ्तार से घटकर 2010-2019 में 9 फीसदी रह गई। बाजार के कई विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2020 मिडकैप व स्मॉलकैप के लिए सुधार का वर्ष हो सकता है। हालांकि हेलियस कैपिटल के संस्थापक और फंड मैनेजर **समीर अरोड़ा** को नहीं लगता कि पहले कुछ महीनों में इन शेयरों में बहुत ज्यादा बदलाव होगा जब तक कि आम बजट में कोई बड़ी राहत मसलन लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की समाप्ति न हो जाए। **जयदीप घोष** को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उस तरह की मानसिक स्थिति में बदलाव की दरकार है जो हर डिफॉल्टर को चोर के तौर पर वर्गीकृत करता है। बातचीत के मुख्य अंश...

आपको क्यों लग रहा है कि दशक के रिटर्न में भारी गिरावट आई है?

भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है क्योंकि 2007 से 2010 के बीच किए गए बड़े निवेश को विभिन्न मुश्किलों जैसे भ्रष्टाचार, न्यायिक सक्रियता, कमजोर क्रियान्वयन, देरी आदि का सामना करना पड़ा। इस वजह से किसी नए बुनियादी ढांचा या पूंजीगत खर्च को लेकर निजी क्षेत्र की पूर्णत: अनिच्छा देखने को मिली।

क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एक अंक में रिटर्न नई व सामान्य बात होगी?

समय के साथ रिटर्न दो अंकों में पहुंचेगा। नॉमिनल जीडीपी वापस 12 फीसदी के दायरे में लौटना चाहिए। साथ ही सेवा व विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां थोड़ी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। इन सभी चीजों से शेयर बाजार का रिटर्न बेहतर होगा।

साल 2019 में सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाई को छू लिया, लेकिन मिडकैप व स्मॉलकैप को झटका लगा। क्या इस साल मिडकैप व स्मॉलकैप की किस्मत में बदलाव होगा?

मुझे नहीं लगता कि पहले कुछ महीने में इनकी किस्मत बदलेगी जब तक कि आम बजट में इक्विटी निवेश को लेकर कुछ अप्रत्याशित कदमों का ऐलान न हो जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की समाप्ति आदि। जब बढ़त रफ्तार पकड़ेगी और फंडिंग में सुधार होगा तो बाजार बेहतर होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहेगा।

इस साल आपकी नजर किन क्षेत्रों पर होगी?

हम मुख्य रूप से तीन थीम में निवेश करते हैं और उसे जारी रखेंगे। ये तीन क्षेत्र हैं - वित्तीय क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र।

विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय परिसंपत्तियों की बिकवाली पर आपने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। लेकिन देसी कंपनियों के पास फंड के अभाव को देखते हुए आखिर क्या समाधान है?

यह पहली मानसिक स्थिति है। अगर हम हर डिफॉल्टर को चोर मान लेंगे तो उन्हें दूसरे स्रोत से रकम मिलने की गुंजाइश काफी कम होगी। जिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में जोखिम समाप्त हो गया है, वे अब एन्युटी वाली परियोजनाओं में हैं जिसे भारतीय पेंशन फंडों को अच्छे देसी मैनेजर के जरिए बेचा जा सकता है, जो ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। लेकिन भारतीय पेंशन फंडों/बीमा कंपनियों को सबसे पहले ऐसी परिसंपत्तियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

सोमवार को आरबीआई का तीसरा विशेष ओएमओ

भारतीय रिजर्व बैंक विशेष ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) का एक और दौर अगले हफ्ते शुरू करेगा। इस बार केंद्रीय बैंक मध्यम व लंबी अवधि के 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्डों की खरीद करेगा और इतनी ही रकम के बॉन्ड बेचेगा, जो इस कैलेंडर वर्ष में परिपक्व होंगे। पिछली दो नीलामी में आरबीआई ने सिर्फ 10 साल के बॉन्ड खरीदे थे, वहीं 2020 में परिपक्व हो रहे बॉन्डों की बिकवाली की थी। इस बार आरबीआई की योजना 2024 और 2019 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड की खरीद करने की है। ओएमओ सोमवार को होगा।

बॉन्ड डीलरों के मुताबिक, बाजार में सीमित उपलब्धता के कारण 10 साल वाले बॉन्डों की खरीद जारी रखना संभव नहीं है। ओएमओ के जरिए लंबी अवधि के प्रतिफल को नीचे लाना और अल्पावधि के प्रतिफल को बढ़ाना है ताकि प्रीमियम स्प्रेड नीचे आ जाए। मध्यम अवधि के बॉन्डों को शामिल करने का मतलब यह है कि ऐसे बॉन्ड का प्रतिफल भी घटेगा। *बीएस*

हटेंगी आरओसी के खिलाफ बाध्यताएं

एनसीएलएटी ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 3 जनवरी तक स्थगित की

रुचिका चित्रावंशी
नई दिल्ली, 2 जनवरी

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को कहा कि वह कंपनी पंजीयक (आरओसी), मुंबई के खिलाफ दिए अपने आदेश से संबंधित बाध्यताएं दूर करने को तैयार है। पंचाट के आदेश में कहा गया था कि टाटा संस को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में तब्दील किया जाना अवैध था और इसमें आरओसी को इसे पलटने का निर्देश दिया गया था।

एनसीएलएटी ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार, 3 जनवरी तक स्थगित कर दी है और आरओसी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर निजी कंपनी का गठन किया गया। एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस के मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय पीठ ने पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में तब्दील किए जाने की अनुमति के लिए प्रक्रिया पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

आरओसी मुंबई ने सितंबर 2017 में टाटा संस को 'पब्लिक' से 'प्राइवेट' कंपनी में तब्दील किए जाने के संबंध में पंचाट के आदेश में 'अवैध' और 'आरओसी की मदद से' शब्दों को हटाए जाने की मांग की थी।

18 दिसंबर के अपने आदेश में एनसीएलएटी ने आरओसी के खिलाफ गंभीर असहमति जताते हुए कहा कि टाटा संस ने 'आरओसी की मदद से' जल्दबाजी में अपना दर्जा पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदला, जो अवैध था।

अपील पंचाट ने आरओसी से प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी चुकता पूंजी के बारे में विवरण मुहैया कराने को कहा है।

अपने 18 दिसंबर के निर्णय में, एनसीएलएटी ने कहा था कि कंपनीज ऐक्ट, 2013 की धारा 14 के तहत पंचाट द्वारा जारी किसी आदेश के बगैर ही आरओसी ने प्रमाणपत्र में 'पब्लिक' शब्द हटा दिया और 'टाटा संस लिमिटेड' को 'प्राइवेट' कंपनी के तौर पर दिखाया।

अपनी याचिका में, आरओसी ने कहा कि फैसले में कुछ तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटियां थीं, और इसलिए अपील पंचाट से आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया गया जिससे कि आरओसी, मुंबई के निर्णय को सही तरीके से पेश किया जा सके।

'बोर्ड सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन है यह आदेश'

देव चटर्जी
मुंबई, 2 जनवरी

टाटा समूह के नेतृत्व वाली कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में दी अपनी याचिका में कहा है कि टाटा समूह के संस्थापक रतन एन टाटा और ट्रस्ट के अन्य नोमिनी को टाटा संस के मामलों में पहले से कोई फैसला लेने से रोकने का एनसीएलएटी का आदेश संदिग्ध है और यह कंपनी के शेयरधारकों और बोर्ड सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन है।

टाटा समूह कंपनियों की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और टाटा इन ट्रस्टों के चेयरमैन हैं। ट्रस्ट के अन्य नोमिनी के साथ टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन से हटाने में अहम योगदान दिया जिससे मिस्त्री और टाटा के बीच तीन वर्ष पुराना टकराव और बढ़ गया।

टाटा संस द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एनसीएलएटी के आदेश में चेयरमैन के चयन से संबंधित टाटा संस के आर्टिकल 118 की बगैर कोई कारण बताए पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

टाटा संस के मामले में, चूंकि टाटा ट्रस्ट्स के पास लगभग 66 प्रतिशत शेयर पूंजी है, लेकिन यह दैनिक प्रबंधन से संबंधित नहीं है और बहुसंख्यक शेयरधारकों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए आर्टीकल 121 शामिल किया गया था। याचिका में कहा गया है, 'एनसीएलएटी के निर्णय ने टाटा संस के आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन को मनमाने ढंग से पेश किया है, जिसमें बहुसंख्यक शेयरधारक अल्पसंख्यकों के अधीन हैं जिससे कॉरपोरेट लोकतंत्र के मूल नियम का उल्लंघन हुआ है।'

लगता है कि एनसीएलएटी इसे लेकर गलत तथ्यों से प्रभावित हुआ है कि मिस्त्री की कंपनियों ने टाटा संस में लगभग 100,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था। मिस्त्री की कंपनियों ने बोनस इश्यू और राइट इश्यू के जरिये अपनी बहुलांश शेयरधारिता खरीदी और टाटा संस की शुरुआती पूंजी के तौर पर सिर्फ 69 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

अदालत में याचिका

- **यह आदेश टाटा समूह के संस्थापक रतन एन टाटा और ट्रस्ट के अन्य नोमिनी को टाटा संस के मामलों में पहले से कोई फैसला लेने से रोकने का एनसीएलएटी का आदेश संदिग्ध है**
- **यह कंपनी के शेयरधारकों और बोर्ड सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन है**
- **ट्रस्ट के अन्य नॉमिनी के साथ टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन से हटाने में अहम योगदान दिया जिससे मिस्त्री और टाटा के बीच तीन वर्ष पुराना टकराव और बढ़ गया**

उच्चतम न्यायालय पहुंचा टाटा

पृष्ठ-1 का शेष

याचिका में कहा गया है कि लीक हुए ईमेल की वजह से स्टॉक एक्सचेंजों और दूसरी नियामकीय संस्थाओं ने भी टाटा की कंपनियों से जानकारी मांगी और टाटा समूह को प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी।

याचिका में कहा गया है कि मिस्त्री को हटाए जाने से पहले टाटा संस की नामांकन एवं पारितोषिक समिति (एनआरसी) ने उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट दी थी लेकिन उसकी राय पूरे टाटा संस बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। एनआरसी में केवल तीन निदेशक थे। मिस्त्री ने अपनी दलील में कहा था कि एनआरसी की अच्छी रिपोर्ट के बावजूद टाटा संस ने टाटा ट्रस्ट्स के न्यासियों के कहने पर उन्हें हटाया था। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66 फीसदी हिस्सेदारी है और टाटा संस के बोर्ड में उसके तीन प्रतिनिधि थे जिनके पास वीटो पावर है।

मिस्त्री को हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले टाटा ट्रस्ट के न्यासियों के बारे में टाटा संस ने कहा कि उनके नामित निदेशक कभी भी टाटा की कंपनियों के प्रभारी नहीं थे।

टाटा संस का प्रबंधन मिस्त्री के हाथों में था जो टाटा समूह की कंपनियों के चेयरमैन भी थे। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मिस्त्री टाटा समूह की कंपनियों का नुकसान कम करना चाहते थे और टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशकों ने उनकी योजना को बट्टा लगाया। इसके उलट मिस्त्री के कामकाज को लेकर सबसे बड़ा असंतोष यह था कि वह विरासत में मिली समस्याओं को दूर करने और टाटा समूह की कंपनियों में सुधार लाने के लिए कोई उचित कदम उठाने में नाकाम रहे।

जेट के लिए अभिरुचि पत्र जमा कराने की तारीख 15 जनवरी

हिंदुजा समूह की निवेश में दिलचस्पी की खबर के बीच जेट एयरवेज के लेनदारों ने अभिरुचि पत्र जमा कराने की तारीख 6 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि सूत्रों ने कहा कि अभी तक कोई नया अभिरुचि पत्र नहीं जमा कराया गया है। इससे पहले लेनदारों ने एक बार फिर अभिरुचि पत्र मंगाने का फैसला लिया था और इसे जमा कराने की आखिरी तारीख 6 जनवरी रखी थी। पहले दौर की बोली प्रक्रिया में इकलौती बोलीदाता के तौर पर उभरी अमेरिका की सिनर्जी समूह की तरफ से समाधान योजना पेश करने में नाकामी के बाद यह देखने को मिला। सिनर्जी समूह ने भी नया अभिरुचि पत्र नहीं जमा कराया है। *बीएस*

निवेश संरक्षण पर ईयू चिंतित

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 2 जनवरी

यूरोपीय संघ (ईयू) से आयात होने वाली शराब और वाहनों पर शुल्कों में कटौती करने की भारत की मंशा के बावजूद समूह इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि भविष्य के द्विपक्षीय समझौतों में निवेश संरक्षण को लेकर उसकी चिंताओं का समाधान किए जाने की जरूरत है।

प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से नहीं जुड़ने का फैसला लेने के बाद भारत ने ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड ऐंड इनवेस्टमेंट एग्रीमेंट (बीटीआईए) पर स्थगित चर्चा को फिर से शुरू करने के लिए ईयू से संपर्क साधा है। लेकिन ईयू के व्यापार नीति निर्माता तब तक इस समझौते पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि भारत भी निवेश संरक्षण पर चर्चा शुरू नहीं करता है। ईयू के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इसे भारत में यूरोपीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख चिंता करार दिया है।

बीटीआईए पर पहली बार 2007 में चर्चा शुरू होने के बाद से 2013 तक 16 दौर की बैठकें हो चुकी थी। राजनयिक ने कहा कि लेकिन यह मामला पूरी तरह से तब ठंडा पड़ गया जब भारत ने 2016 में 23 यूरोपीय देशों के साथ मौजूदा द्विपक्षीय निवेश निवेश समझौतों (बीआईटी) को रद्द करने का निर्णय ले लिया। तब ईयू ने भारत को चेताया था कि उसके इस कदम से ईयू के सदस्य देशों से यहां पर होने वाल निवेश रुक जाएगा और भारत को नए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक इन व्यक्तिगत समझौतों को जारी रखने के लिए कहा था।

हालांकि सरकार इस बात पर कायम है कि भविष्य में होने वाले सभी निवेश समझौतों पर चर्चा सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए मॉडल बीआईटी के ढांचे के तहत होगी। इसे दूसरे देशों के साथ व्यक्तिगत व्यापार समझौतों पर चर्चा का आधार बनाने हेतु लाया गया था।

हालांकि, 2016 में एकतरफा कदम उठाते हुए निवेश समझौतों को रद्द करने के बाद के चार वर्ष में बांग्लादेश, बेलारूस, कोलंबिया और ताइवान के साथ कुल मिलाकर केवल चार बीआईटी ही पूरे हुए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि बातचीत को समयबद्ध नहीं किया गया है अत: उसे पूरा करने की कोई समयसीमा नहीं है। फिलहाल 11 अन्य देशों के साथ वार्ता चल रही है। ईयू राष्ट्रों में नीदरलैंड भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चौथा सबसे बड़ा देश है। नीदरलैंड ने वर्ष 2000 से 29 अरब डॉलर का निवेश किया है। दूसरी तरफ जर्मनी, साइप्रस और फ्रांस एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इनमें ब्रग्जिट का सामना कर रहे यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है।

दिल्ली के एक वरिष्ठ व्यापार विशेषज्ञ ने कहा, 'बीआईटी को लकर ईयू की प्रमुख चिंता उस उपनियम को लेकर जिसमें कहा गया है कि निवेशक और सरकार के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में विदेशी निवेशक अंतरराष्ट्रीय पंचाट में जाने का विकल्प केवल तभी अपना सकता है जब सभी घरेलू कानूनी रास्ते बंद हो चुके हों। भारत को यह कदम मुकदमेबाजी को नियंत्रित रखने के लिए और अंतरराष्ट्रीय पंचाटों से अत्यधिक जुर्माने की गुंजाइश को सीमित रखने के लिए जरूरी लगता है तो वहीं ईयू ने भारत की न्याय प्रणाली को धीमा और भ्रष्ट करार दिया है।'

शुल्क कटौती से नहीं बनेगी बात

भारत इस बात पर कायम है कि भविष्य में होने वाले सभी निवेश समझौतों पर चर्चा सरकार द्वारा 2015 में जारी किए गए मॉडल बीआईटी के ढांचे के तहत होगी

- ईयू ने की द्विपक्षीय समझौते के लिए निवेश संरक्षण पर चर्चा की मांग
- भारत ने अवगत कराया है कि यूरोप से आयातित शराब और वाहन पर शुल्कों में कटौती की जा सकती है
- बीटीआईए पर 2007 में चर्चा शुरू होने के बाद से 2013 तक 16 दौर की बैठकें
- 2016 में 23 यूरोपीय देशों के साथ मौजूदा बीआईटी को रद्द करने के भारत के फैसले के बाद से चर्चा बंद

जीएसटी पर राजस्व सचिव की 7 जनवरी को बैठक

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 2 जनवरी

वित्त वर्ष 2019-20 के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के कठिन लक्ष्य के बीच राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय मंगलवार को कर आयुक्तों के साथ एक दिन की बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में जीएसटी प्रणाली को तार्किक बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि राज्य कर विभाग के आयुक्तों और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ जीएसटी अनुपालन बढ़ाने, खामियां दूर करने, कर चोरों को हतोत्साहित करने पर विचार होगा, जो इस व्यवस्था का दुरुपयोग या गलत लाभ उठा रहे हैं।

यह बैठक इस हिसाब से भी अहम है कि जीएसटी परिषद ने 18 दिसंबर को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में इच्छा जताई थी कि वस्तुओं पर कर बढ़ाने के किसी फैसले के पहले इन मसलों पर विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए। दिसंबर महीने में लगातार दूसरी बार मासिक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन 2019-20 का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिसंबर से लेकर वित्त वर्ष के शेष महीनों में हर महीने 1.10 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह की जरूरत है। दरअसल इन चार महीनों में से किसी एक महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह की जरूरत होगी। सूत्रों ने कहा कि विभिन्न पहलुओं को लेकर प्रस्तावित इस लंबी बैठक का मकसद धोखाधड़ी और कर चोरी रोकना, फर्जी या बहुत ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावों की जांच, कारोबारियों के बैंक खातों के विस्तृत ब्योरे की मांग, जिससे किन उनकी फाइलिंग से मिलान किया जा सके, रिफंड के दुरुपयोग और राजस्व संग्रह में बेहतर तरीकों का इस्तेमाल पर विचार करना है।

इस बैठक में ई-इन्वॉयसिंग, नई रिटर्न व्यवस्था और फीडबैक, ईवे बिल को फास्टैग से जोड़ने, रिफंड लंबित होने, जीएसटी पंजीकरण को आधार से जोड़ने, बगैर पहुंचे प्रवर्तन के तरीके, क्यू आर कोड आदि जैसे आगे के मसलों पर भी चर्चा होनी है। सूत्रों ने कहा कि डेटा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा के अधिक इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे कर चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और बेहतर कर अनुपालन से राजस्व बढ़ाया जा सके। इसमें बैंकों, आईएफयू इंडिया जैसे तीसरे पक्ष के आंकड़ों के संयुक्त अध्ययन आदि पर चर्चा होगी।

ओएएलपी के चौथे दौर में ओएनजीसी को सभी ब्लॉक

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 2 जनवरी

सरकार ने आज तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को सभी 7 ब्लॉक आवंटित कर दिए हैं। इनकी पेशकश ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के चौथे दौर में की गई थी।

मौजूदा दौर के बाद देश के कुल अन्वेषण क्षेत्र में 18,510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और जुड़ गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि पांचवें चरण के तहत और 20,000 किलोमीटर क्षेत्र के लिए बोली को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इन 7 ब्लॉकों में 5 ब्लॉक मध्य प्रदेश में हैं, जबकि राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 1-1 ब्लॉक हैं।

ये 7 ब्लॉक 3 तलछल वाले बेसिन में फैले हैं, जिनमें कु ल 33 अरब बैरल तेल और तेल के बराबर गैस संसाधन होने की क्षमता है। पहले 4 दौर में अगले 3 से 4 साल में अन्वेषण से जुड़े काम में करीब 2.35 अरब डॉलर निवेश होने की संभावना है।

प्रधान ने कहा, 'पिछले 2 वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के अन्वेषण व उत्पादन के लिए सरकार ने सफल बोली आयोजित की है। इसके साथ ही इन वर्षों में हमने कई बार अपनी नीतियों में सुधार किया है।' दिलचस्प है कि 2018 तक सिर्फ 90,000 वर्गकिलोमीटर अन्वेषण के तहत आता था। ओएलएपी के पहले दौर में 55 ब्लॉक आवंटित किए गए थे। दूसरे और तीसरे दौर में 32 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिसके लिए संयुक्त रूप से आवंटन का काम हुआ।

इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 102 लाख करोड़ रुपये की नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) का अनावरण किया था, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रधान ने कहा, 'हम देखेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अनुमानित निवेश की तुलना में ज्यादा निवेश आएगा।'

नए ऑर्डर से सात माह बाद विनिर्माण गतिविधियां तेज

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 2 जनवरी

नए ऑर्डर में अचानक तेजी की वजह से संकट से जूझ रहे विनिर्माण क्षेत्र में दिसंबर महीने में तेजी आई है। हालांकि कारोबारी धारणा 3 साल के निचले स्तर पर है क्योंकि बाजार की कमजोर स्थिति से फर्में आशंकित हैं। एक मासिक वैश्विक सर्वे में यह सामने आया है।

निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेज मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नवंबर के 51.2 से बढ़कर दिसंबर में 7 महीनों के उच्च स्तर 52.7 पर पहुंच गया है। पीएमआई 50 से ऊपर होने का मतलब विस्तार जबकि इससे नीचे रहने पर कारोबार घटने का संकेत होता है। अक्टूबर में पीएमआई 2 साल के निचले स्तर 50.6 पर पहुंच गया था।

बहरहाल आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर तक विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन बना रहा। अक्टूबर महीने में भारत का कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन 3.8 प्रतिशत गिरा, जबकि सितंबर महीने में 8 साल का सर्वोच्च 4.3 प्रतिशत संकुचन था।

वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन नवंबर में लगातार तीसरे महीने में गिरा है और यह 1.5 प्रतिशत नीचे रहा। इसके पहले के दो महीने में उत्पादन रिकॉर्ड 5.8 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत गिरा है क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई।

लेकिन दिसंबर में पीएमआई ने बेहतर तस्वीर दिखाई है। फैक्टरियों का उत्पादन 10 महीने के उच्च स्तर पर रहा। इसमें मुख्य भूमिका नए ऑर्डर बढ़ने की रही, जो जुलाई के बाद सबसे तेज रहा। कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया और उसके लिए भर्तियां भी हुईं।

उप सेक्टर के स्तर पर देखें तो इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका उपभोक्ता वस्तुओं की रही। इंटरमीडिएट गुड्स ने भी मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन सर्वे मे कहा गया है कि पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में सुस्ती बनी रही। जिन कंपनियों ने वृद्धि दिखाई है, उनके नए ऑर्डर में बढ़ोतरी, नए उत्पाद पेश करने और तकनीक में सुधार की प्रमुख भूमिका रही है। नए काम जुलाई के बाद सबसे तेजी से बढ़े हैं और नए उत्पादों व बेहतर मांग की स्थिति ने बाजार में सफलता दिलाई है। बहरहाल नए निर्यात ऑर्डर की बिक्री बढ़ाने में भूमिका बहुत कम रही है।

रेस्टोरेंट मालिकों व एग्रीगेटरों में फिर छिड़ सकती है जंग

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 2 जनवरी

रेस्टोरेंट मालिकों और उनके एग्रीगेटरों के बीच एक बार फिर कमीशन को लेकर जंग छिड़ सकती है क्योंकि खाना ऑर्डर करने वाले ऐप अपना कमीशन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट अभी कमीशन बढ़ने की पुष्टि करने में लगे हैं, वहीं उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो वे एग्रीगेटरों की सेवा बंद कर सकते हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर स्विगी और जोमैटो अपना कमीशन 5 से 10 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इस समय एग्रीगेटर अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े रेस्टोरेंट से 5 से लेकर 40 प्रतिशत तक कमीशन ले लेते हैं।

नैशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष अनुराग कत्रियार ने कहा, 'हमने कमीशन बढ़ाए जाने के बारे में कुछ सदस्यों से सुना है, लेकिन किसी एग्रीगेटर ने हमसे सीधे संपर्क नहीं किया है। हम अब अपने सदस्यों से व्यापक सूचना मांग रहे हैं। उनके फीडबैक पर हमारी आगे की कार्रवाई निर्भर होगी।'

बहरहाल एग्रीगेटरों ने इस तरह की किसी योजना से इनकार किया है। स्विगी के प्रवक्ता ने कहा, 'स्विगी इससे इनकार करकती है कि किसी खास रेस्टोरेंट साझेदार के कमीशन में कोई अस्वाभाविक बढ़ोतरी की गई है। कमीशन रेस्टोरेंट के स्तर पर औसत ऑर्डर मूल्य, डिलिवरी लागत और अन्य लागतों पर निर्भर होता है। हर समझौते का नवीकरण पहले से तय समय ढांचे के मुताबिक होता है।'

बीएस सूडोकू 3629

		8		6		1		
	1	7			5			
		6					9	
	6			8				4
		3	1		4	9		
4				2			7	
	7					5		
			5			7	3	
		9		3		2		

परिणाम संख्या 3628

6	3	5	2	8	9	7	4	1
7	8	2	4	1	6	9	5	3
9	1	4	5	3	7	2	8	6
4	7	8	3	9	1	6	2	5
5	9	1	6	4	2	3	7	8
2	6	3	8	7	5	1	9	4
1	5	6	9	2	4	8	3	7
3	2	7	1	5	8	4	6	9
8	4	9	7	6	3	5	1	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2205/2210, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1650/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2210/2220, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1443, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1522, फ्लैक 1462, डीएमओ 1051, टरपीन लैस बोल्ड 1548

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1300/1380, खुरपा 1200/1250,चाकू 1250/1300, रसकट 1000/1020, शक्कर 1380/1400, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1300/1390, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खल: सरसों 2300/2400, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2240/2250, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4890/4900,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2100/2125, ग्वार 3950/4000, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2150, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7700/7800, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4350/4450, काबली चना 5100/6000, मूंग 6400/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)132, राइसब्रान (अखाद्य) 127, खल सरसों 2100, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1325,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5550, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4030/4070, हरियाणा 4000/4030, राजस्थान 3950/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2250/2260,

फाजिल्का
गेहूं 2265/2275, सरसों 4700/4800 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4150, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5400/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2280/2290, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2500/2525, दाल उड़द छिलका 9500/10900, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5500/5700, काबली चना 5300/6200, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7900/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2230/2240, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5200, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 39000/3950, जौ 1775/1780, सरसों 4350/4400, मूंग 6500/6700, गेहूं 2160/2165,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1100/1110, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4450/4500, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3400, सरसों तेल 9650/9700, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3950/4000, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 273

पटरी पर रेलवे

भारतीय रेलवे ने मंगलवार को यात्री किराये के आधार मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि अर्द्ध-शहरी इलाकों में चलने वाली लोकल ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी तरह की यात्राओं पर लागू होगी। किराये में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, प्रति किलोमीटर सफर पर एक पैसे से लेकर चार पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी और गैर-एक्सप्रेस ट्रेनों की गैर-वातानुकूलित श्रेणियों का किराया प्रति किलोमीटर एक पैसे बढ़ा है जबकि वातानुकूलित श्रेणियों का किराया प्रति किलोमीटर चार पैसे बढ़ाया गया है। इस तरह राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट मूल्य में हुई वृद्धि भी 100 रुपये से कम ही है। वहीं मासिक टिकट धारकों के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस किराया वृद्धि को लेकर थोड़ा शोर हो सकता है लेकिन सच यह है कि यह जरूरी कदम का एक हिस्सा भर है।

भारतीय रेलवे अपने हालिया इतिहास के कुछ सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। रेलवे के लिए अहम वित्तीय आंकड़ा परिचालन अनुपात का है। इसका मतलब परिचालन व्यय के बरक्स परिचालन राजस्व का अनुपात होता है। चालू वित्त वर्ष में यह अनुपात पहले ही सौ फीसदी के स्तर से आगे निकल चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो रेलवे खतरे की जद में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की गत महीने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 दोनों साल एनटीपीसी और रेलवे के पूर्व उपक्रम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने अग्रिम भुगतान कर उसे संकट से उबारा था। सीएजी ने इंगित किया था कि रेलवे के राजस्व अधिशेष में लगातार गिरावट देखी गई है और अपने पूंजी व्यय में आंतरिक संसाधनों की उसकी हिस्सेदारी भी घटी है। राजस्व जुटा पाने में इस नाकामी का बोझ रेलवे नेटवर्क और आम करदाता को उठाना पड़ा। विस्तारित मूल्यह्रास के जरिये रेल नेटवर्क और केंद्रीय बजट समर्थन पर रेलवे की बढ़ती निर्भरता के जरिये आम करदाता ने यह बोझ उठाया।

जहां इस वित्त वर्ष में अब तक कोई बड़ा रेल हादसा नहीं हुआ है वहीं अपनी अवधि पूरा कर चुकी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण का काम टालने से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। ऐसे में रेलवे की वित्तीय सेहत बहाल करना निस्संदेह तात्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए। सच यह है कि यात्रियों को भुगतान करना होगा। पहले से ही मालढुलाई से मिलने वाला लगभग सारा राजस्व यात्री किराये की क्रॉस-सब्सिडी में चला जा रहा है। लंबी दूरी की वातानुकूलित चेयरकार सेवा अपना खर्च खुद निकाल लेती है लेकिन कई दूसरी यात्रा श्रेणियां घाटे में ही हैं। शहर के भीतर चलने वाली लोकल ट्रेनों को भी किराया वृद्धि से हमेशा के लिए छूट नहीं दी जा सकती है।

निचोड़ यह है कि रेलवे की परिचालन स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के लिए इसका पुनर्गठन जरूरी हो चुका है। कर्मचारियों के विरोध को अनसुना करते हुए सरकार ने रेलवे कैडरों का पुनर्गठन कर अपनी आंतरिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। लेकिन उसे और आगे बढ़ने की जरूरत होगी। रेलवे के वाणिज्यिक हितों को सरकार के सामाजिक दायित्वों से अलग करने के लिए एक प्रणाली बनाना अहम है। अगर सरकार रेलवे पर सामाजिक दायित्व थोपना चाहती है तो उसके लिए रेलवे को पूरा मुआवजा देना होगा और उसे इतर गतिविधियों में रेलवे को किसी लाभपरक कंपनी की तरह काम करने की छूट देनी होगी। इससे रेलवे को अपना निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी और अधिक तेजी से मालढुलाई कर वह अर्थव्यवस्था की क्षमता वृद्धि में भी योगदान कर सकेगा।

रेल मंत्रालय को समुचित स्वतंत्रता की जरूरत है जो असल में एक होल्डिंग कंपनी के सुपुर्द की जानी चाहिए। सच तो यह है कि व्यापक सुधारों के अभाव में रेल वित्त एवं निवेश पर असर पड़ना जारी रहेगा।

बिनय सिन्हा

न्यायिक क्षेत्र में आईबीसी की बेहतर समझ जरूरी

वरिष्ठ न्यायाधीशों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि कैसे उनके फैसलों का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **जैमिनी भगवती**

बीती कुछ तिमाहियों से देश की आर्थिक तस्वीर खस्ता ही नजर आ रही है। वृद्धि में आए धीमेपन की प्रकृति के चक्रीय या ढांचागत होने को लेकर जो बहस हो रही है वह मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली है। इस आलेख में हम व्यापक चिंताओं से परे इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए दीर्घावधि के ऋण के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी बैंक अभी भी परियोजनाओं को ऋण देने में हिचकिचा रहे हैं। वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अल्पकालिक ऋण देने में भी हिचक रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 24 दिसंबर को 'रिपोर्ट ऑन ट्रेंड ऐंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19' जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत निस्तारण की समय सीमा को बढ़ाकर 330 दिन कर दिया गया है लेकिन कुछ मामलों में इस सीमा से भी अधिक देरी हो रही है क्योंकि बार-बार वाद हो रहे हैं।

आरबीआई की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का तीव्र गति से निस्तारण किया जाए। यह भी कहा गया है कि सरकारी बैंकों की ऋण वृद्धि बीते कुछ वर्षों के दौरान निजी बैंकों से कमतर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर 2019 के अंत तक सरकारी बैंकों का कुल फंसा हुआ कर्ज कुल बकाये का 12 फीसदी था। सरकारी बैंकों को इसे 10 फीसदी से कम करना होगा तभी लंबी अवधि का ऋण स्तर हासिल हो सकेगा। बेहतर निगरानी के लिए देश में बेहतर पूंजी वाले दो सरकारी बैंकों की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि आईबीसी सही ढंग से काम कर रही है। बहरहाल सरकारी बैंकों की मौजूदा सतर्कता बताती है कि ऋण से जुड़े जोखिम और बाद में सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा बैंक प्रबंधकों के साथ कड़ाई करने को लेकर जोखिम बरकरार हैं। वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में दोषसिद्धि मुश्किल होती है। यही कारण है कि आपराधिकता को लेकर जांच जारी रहती है। ऐसे में व्यावहारिक कदम यही है कि परिसंपत्ति को बरकरार रखा जाए क्योंकि चालू परिसंपत्ति वैकल्पिक निवेशकों को भी आकर्षित करती है।

कई प्रवर्तक पहले अपनी ऋण आवश्यकताओं को बढ़ाचढ़ाकर पेश करते हैं और बाद में अंतहीन कानूनी चुनौतियों के माध्यम से अपनी निस्तारण प्रक्रिया को जटिल बना लेते हैं। वे निस्तारण पेशेवरों की नियुक्ति का यह कह कर विरोध करते हैं कि उनके पास काबिलियत नहीं है या वे पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं। ऐसा करके वे ऋणदाताओं की समिति में मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं। अगर ये तरीके नाकाम साबित होते हैं तो वे राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील पंचाट (एनसीएलएटी)की शरण लेते हैं और आखिर में सर्वोच्च न्यायालय की।

एस्सार स्टील ऋण डिफॉल्ट मामले को देश के कानून और कारोबारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस घटना में ऋणदाताओं ने एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर-मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की बोली को स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट (एनसीएलटी) ने मार्च 2019 में स्वामित्व में इस बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी। एस्सार ने एनसएलटी के इस निर्णय के खिलाफ अपील की कि आर्सेलर की पेशकश का 90 फीसदी हिस्सा एनएसीएलएटी के जरिये वित्तीय ऋणदाताओं को जाएगा। एनसीएलएटी ने कहा कि सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को संचालन ऋणदाताओं के समकक्ष माना जाना चाहिए और वित्तीय ऋणदाताओं को चुकाई जाने वाली राशि को 42,000 करोड़ रुपये के 65 प्रतिशत पर सीमित किया जाना चाहिए। 14 नवंबर के एक अहम फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीएलएटी के निर्णय बदल दिया और कहा कि ऋणशोधन प्रक्रिया में संपत्ति वितरण का निर्णय कर्जदार कर सकते हैं। इस फैसले ने आर्सेलर मित्तल के एस्सार स्टील को अधिग्रहीत करने की राह आसान की और आईबीसी को कठिनाई से उबारा।

डिफॉल्ट का हर मामला अलग होता है। पुराने प्रवर्तक मामले को जटिल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी परिसंपत्ति कर्जमुक्त होकर और सस्ती कीमत पर उनके अलावा किसी को न बिके। एस्सार स्टील मामले में एनसीएलएटी का निर्णय यह संकेत देता है कि पुराने मालिकों में यह स्टेमिना और संसाधन है कि वे अपनी परिसंपत्ति बचाने के लिए लड़ सकें। देश की न्याय व्यवस्था इस आधार पर प्रवर्तकों के पक्ष में नजर आती है कि कामगारों के हित को देखते हुए कारोबार चलता रहे।

आईबीसी अब बहुत अधिक कठिनाई में नहीं है लेकिन अभी भी उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ऋणदाता समिति का कर्ज को बट्टे खाते में डालने के लिए एक ढांचे पर सहमत होना और निस्तारण पेशेवरों की विश्वसनीयता का प्रश्न हल करना शामिल है। भूषण पावर ऐंड स्टील का मामला बताता है कि देरी इसलिए भी होती है क्योंकि आईबीसी तथा उससे पहले के विवाद उभर आते हैं। दिसंबर 2019 तक आईबीसी के 1,500 मामले ऋणदाता समिति, निस्तारण प्रतिनिधियों तथा अदालतों के पास लंबित हैं। आईबीसी की व्याख्या में न्यायिक अंतर को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और अन्य विधानों के साथ असंगतता के चलते इसमें बार-बार संशोधन किया गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मूल्यांकन की अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके और यह स्पष्ट किया जा सके कि अंतिम बिक्री में किसे क्या हिस्सेदारी मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के न्यायाधीशों को विषय विशेषज्ञों द्वारा इस विषय में गहरी जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वे विभिन्न प्रकार के ऋणशोधन की प्रकृति और परिणाम से अवगत हो सकें। अनुभवी न्यायाधीश इस विचार से नाराज हो सकते हैं कि उन्हें ऐसे मामलों के आर्थिक प्रभाव की बेहतर समझ पैदा करनी होगी। जबकि यह सही है कि प्रवर्तक व अन्य पक्षकार ऐसे मामलों को अपने पक्ष में करने के लिए जुगत लगाते हैं। व्यापक जनहित में सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि वह न्यायिक निर्णय से पहले ऐसी ब्रीफिंग को अनिवार्य बना दे।

लब्बोलुआब यह है कि गलत निर्णय और धोखाधड़ी से भरे ऋणशोधन प्रक्रिया के मौजूदा मामले यह बताते हैं कि देश में वित्तीय मध्यस्थता के बेहतर नियमन की आवश्यकता है। इसके अलावा ऋणशोधन प्रक्रिया की गति भी तेज करने की जरूरत है। आरबीआई को बैंकों और एनबीएफसी को भी इस विषय में अवगत कराना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय में 12 फरवरी, 2018 का परिपत्र सामने करना चाहिए जिसमें ऋणदाताओं को डिफॉल्ट के मामलों को एनसीएलटी के समक्ष ले जाने के लिए कमतर समय सीमा दी गई है। स्वतंत्रता की तरह समझदारी भरी बैंकिंग के लिए भी शाश्वत सतर्कता के साथ-साथ वित्तीय और आर्थिक मुद्दों की बेहतर समझ की आवश्यकता होती है।

नया साल गुजरे साल से कम निराशाजनक होने की उम्मीद

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

वर्ष 2019 के निराशाजनक ढंग से खत्म हो जाने के बाद वर्ष 2020 से तमाम उम्मीदें लगी हैं। क्या नया साल भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक पाएगा? और पिछले साल अधिकांश समय अपने सियासी एजेंडे पर ही टिकी रही नरेंद्र मोदी सरकार इस साल अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देगी? वर्ष 2020 में मोदी सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, भविष्यवाणी करना तो दूर की बात है। नए साल में प्रमुखता से सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों की सूची तैयार करना कहीं अधिक सुरक्षित होगा। यहां पर तीन ऐसे मुद्दों या घटनाओं की सूची है जो अगले 12 महीनों में घटित हो सकते हैं।

एयर इंडिया बन जाएगी इतिहास: अगर अधिकारियों पर यकीन करें तो सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया जून 2020 के बाद वजूद में नहीं रहेगी। मोदी सरकार इस बात की पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसे किसी निजी एयरलाइन को बेच दिया जाए लेकिन इसका कोई खरीदार ही नहीं दिख रहा है। अगर जून तक खरीदार सामने नहीं आता है तो सरकार एयर इंडिया का परिचालन बंद कर देगी। इसके पायलटों ने पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा है कि एयर इंडिया को बंद करने के पहले उनके वेतन एवं अन्य भत्तों के बकाये का भुगतान किया जाए।

एयर इंडिया की बंदी देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक दौर के अंत की निशानी होगी। इस एयरलाइन को टाटा ने शुरू किया था और कुछ समय तक इसका संचालन भी किया। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में कमी, उसकी अक्षमता में वृद्धि और घाटा बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि समय के साथ सरकारी खजाने पर उसकी निर्भरता बढ़ती चली गई।

लेकिन मोदी सरकार ने 2017 के मध्य में यह फैसला किया कि एयर इंडिया का निजीकरण किया जाएगा। लेकिन बिक्री के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ऐसी थी कि उसका नाकाम होना तय था। दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इसके निजीकरण की कोशिश फिर शुरू कर दी है लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली है। अब कहा जाने लगा है कि जून में इसे बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह इसकी तस्दीक करेगा कि सरकारों ने एयर इंडिया को किस तरह लगातार नजरअंदाज किया है और अपनी एक परिसंपत्ति को नष्ट होने दिया। अगर निजीकरण की कोशिश पहले की गई होती और जमीनी धरातल पर रहते हुए आकर्षक पेशकश की गई होती तो एयर इंडिया अपने बदतर भविष्य से बच सकती थी।

बजट से दिखेगी सरकारी वित्त की सही तस्वीर: एक महीने बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से यह साफ संकेत मिलेगा कि सरकार सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि से किस तरह निपटना चाहती है। वह राजकोषीय मजबूती की जरूरत को ध्यान में रखते हुए करों में कटौती या ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने या दोनों तरीकों के मिश्रित इस्तेमाल में से किसे आजमाती हैं।

हालांकि बजट से अधिक स्पष्ट होने वाली बात सरकारी वित्त की सही स्थिति से जुड़ी होगी। इसमें पहली बार यह स्वीकारोक्ति होगी कि वर्ष 2018-19 में वास्तविक सकल कर राजस्व संग्रह 2019 के बजट में पेश संशोधित अनुमानों से भी काफी कम रहा था। सरकार की गैर-बजट उधारियों की सच्ची तस्वीर भी इस बजट से पता चल सकेगी। अपने व्यय के लिए सरकार ने अपने प्रमुख राजकोषीय घाटे आंकड़े पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अतीत में गैर-बजट उधारियां की थीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट 2020 गैर-बजट उधारियों या कल्पनाशील लेखांकन का रास्ता अपनाए बगैर हासिल राजकोषीय घाटे के बारे में अधिक वास्तविक तस्वीर पेश करता है या नहीं।

जीएसटी परिषद की बैठकें होंगी हंगामेदार: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की नई दिल्ली में गत महीने हुई बैठक ने यह दिखाया कि आने वाले महीनों में इसकी चर्चाएं कितनी हंगामाखेज होंगी? परिषद की 38वीं बैठक में लॉटरी दरें तय करने का फैसला होना था। इसके लिए परिषद के इतिहास में पहली बार मतदान का तरीका आजमाया जाना था। तीन वर्षों के अपने वजूद में जीएसटी परिषद में सारे निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए गए थे।

लेकिन पिछले कुछ महीनों में देश की सियासत बदल गई है। अब केवल 17 राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारें रह गई हैं। जीएसटी परिषद में 29 राज्यों और दो केंद्रशासित क्षेत्रों- दिल्ली एवं पुदुच्चेरी को मताधिकार मिला हुआ है। हालांकि राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के मत का मूल्य 2:1 है। अगर किसी निर्णय पर सहमति नहीं बनती है तो परिषद में मतदान होगा। बैठक में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई मत पाने पर ही प्रस्ताव स्वीकृत हो सकेगा। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार को अकेले ही 33 भारांक हासिल है। हालांकि मोदी सरकार जीएसटी परिषद की बैठकों में भाजपा-शासित 17 राज्यों पर भरोसा कर सकती है। लेकिन इनका समर्थन मिलने के बाद भी उसके पास 69 अंक ही हो पाएंगे। यानी उसे कोई फैसला लेने के लिए फिर भी छह मतों का इंतजाम करना होगा। इस तरह जीएसटी परिषद की बैठक में उसे कम-से-कम तीन अन्य राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। इतना तो तय है कि 2020 में जीएसटी परिषद की बैठकों में अधिक विवाद होंगे और केंद्र सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप चलने के लिए मजबूर होगा।

वर्ष 2020 में ये तीनों मसले यह दिखाएंगे कि नया साल भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ शासन के लिए भी कितनी नई चुनौतियां पेश करने वाला है? अगर सरकार इन घटनाओं से जल्द सही सबक सीखती है तभी यह सोचा जा सकता है कि 2019 की तुलना में 2020 का अंत उतना निराशाजनक नहीं होगा।

कानाफूसी

नाराजगी भरा विस्तार

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) तथा कांग्रेस गठबंधन के विधायकों में नाराजगी चल रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में पुणे स्थित कांग्रेस भवन पर हमले के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम थोपटे के समर्थक थे जिन्हें राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार के समय मंत्री पद नहीं दिया गया। थोपटे पूर्व मंत्री अनंतराव थोपटे के पुत्र हैं। मंत्रिमंडल से बाहर हुए दूसरे नेता तथा विधायकों ने अलग-अलग तरीकों से नाराजगी जाहिर की। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के बीड जिले की माजलगांव सीट से राकांपा के चार बार के विधायक प्रकाश सोलंकी ने अपनी सीट छोड़ने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद विधायक के तौर पर बने रहने का निर्णय लिया।

प्रियंका का जुर्माना

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 28 दिसंबर को जिस स्कूटर की पीछे की सीट पर बैठी थीं और बाद में उसपर 6,300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था, उस स्कूटर के मालिक राजदीप सिंह ने स्वयं यह जुर्माना भरने का निर्णय लिया है। सिंह के स्कूटर को कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर चला रहे थे ताकि वह प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी तक पहुंचा सकें। दारापुरी को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान गुर्जर तथा वाड्रा ने हेलमेट को बिना सफर करते हुए देखा गया था। सिंह का कहना है कि उन्हें मीडिया से इस जुर्माने का पता चला। उन्होंने कहा, 'मैं स्वयं इस राशि का भुगतान करूंगा। मैं इसे प्रियंका या कांग्रेस से नहीं ले सकता।'

आपका पक्ष

नए साल में महंगाई का तोहफा

वर्ष 2020 शुरू होते ही सरकार ने रेल किराये और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर महंगाई का तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने भी राज्य में बिजली दरों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को महंगाई का झटका दिया है। ये चीजें आम लोगों के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार को इन सुविधाओं को आम लोगों तक समय पर और आरामदायक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए भारी खर्च करना पड़ता है, लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियां भी महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। सरकार अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए गरीबों को कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने की योजनाएं लाती हैं लेकिन वे महंगाई बढ़ाने का काम करती हैं। मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घरों तक रसोई गैस पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर कुछ गरीबों की रसोई से गैस को दूर करने का काम भी कर रही है। मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना से गांवों को रोशन किया, लेकिन पंजाब सरकार बिजली दरों में वृद्धि कर सामान्य लोगों के घरों में अंधेरा करना चाहती है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार अपनी जेब से कोई मुफ्त की सुविधा नहीं देती है। मुफ्त की सेवाओं का आर्थिक बोझ जो सरकारों पर पड़ता है उसकी भरपाई सरकार महंगाई बढ़ा कर करती हैं। आज रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए मोदी सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए तभी अच्छे दिन आ सकेंगे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सरकार ने नए साल से रसोई गैस, विमानन ईंधन और रेल किराये में बढ़ोतरी की

एक अलग कंपनी बने

भारतीय रेल अब अधिक कुशल हो रहा है। उदाहरण के लिए आईआरसीटीसी ने हाल में अपना आईपीओ जारी कर बाजार से अच्छा धनोपार्जन किया है। इसी तर्ज पर रेल पटरियों और पुलों पर भी काम होना चाहिए। घिसी पिटी पटरियों के निस्तारण और जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण के लिए रेल को अलग सक्षम कंपनी चाहिए जो न केवल पटरियों का निर्माण करे बल्कि उसे बिछाने, रखरखाव करने, बोली लगाकर अप्रयुक्त पटरी का निपटान भी करे। अभी पटरी के लिए रेल भिलाई स्टील प्लांट पर निर्भर है।

हिम्मत जोशी, नागपुर

बढ़ाना होगा भाईचारा

देश को आजाद कराने के लिए सभी ने सहयोग किया था। लेकिन वर्तमान में समाज में कुछ अलग स्थिति देखने को मिल रही है। राजनीति भी ऐसी हो रही है जो हिंसा फैलाने का काम कर रही है। देश में इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है उससे आम जनमानस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हिंसा के परिणाम हमेशा घातक रहे हैं जो समाज और देश दोनों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को समाज में चलने वाले राजनीतिक स्टंट को समझना होगा क्योंकि राजनीति हमेशा अपना हित देखती है। वर्तमान की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। आम लोगों को इसके प्रति सचेत रहना होगा। हमें नफरत को छोड़कर भाईचारे और आपसी सौहार्द की राह पकड़नी होगी। नफरत फैलाने वालों की साजिशों को अपनी आपसी समझदारी से जवाब देना होगा। युवाओं को भी भटकाव से बचाना होगा।

मो. जमील, मधुबनी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

अप्रैल-नवंबर में सोने का आयात 7 फीसदी गिरा

देश का सोना आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 7 प्रतिशत गिरकर 20.57 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.16 अरब डॉलर था। सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। 2019-20 के अप्रैल-नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 106.84 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर पर था। सोने के आयात में इस साल जुलाई से ही नकारात्मक वृद्धि है। हालांकि अक्टूबर में यह करीब 5 प्रतिशत बढ़कर 1.84 अरब डॉलर और नवंबर में 6.6 प्रतिशत बढ़कर 2.94 अरब डॉलर रहा।

भारत दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है और मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। देश का सालाना स्वर्ण आयात 800-900 टन है। सरकार ने व्यापार घाटा और चालू खाते के घाटे पर सोने के आयात के नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया था। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में काम कर रही कंपनियां उच्च शुल्क के कारण अपना विनिर्माण आधार पड़ोसी देशों में स्थानांतरित कर रही हैं। *भाषा*

चौथे महीने भी बढ़े इस्पात के दाम

अदिति दिवेकर और टी ई नरसिम्हन
मुंबई/चेन्नई, 2 जनवरी

घरेलू इस्पात उत्पादकों ने लागत के दबाव और मांग बढ़ने के कारण जनवरी के लिए अपने उत्पादों के दाम 1,000 से 1,500 रुपये प्रति टन तक बढ़ाए हैं। जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेएसपीएल) के प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'लौह अयस्क खनिकों ने दाम 600 रुपये प्रति टन बढ़ा दिए हैं, जिससे इस्पात उत्पादन की लागत 1,000 रुपये प्रति टन बढ़ गई है। इस लागत दबाव के कारण जनवरी लगातार चौथा ऐसा महीना है, जब घरेलू इस्पात कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तगड़ा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, जिससे घरेलू बाजार में इस्पात की खपत बढ़ने के आसार हैं। आने वाले महीनों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस्पात की मांग बढ़ने की उम्मीद में आज सभी इस्पात कंपनियों के शेयरों की कीमतें चढ़ीं (चार्ट देखें)। जेएसडब्ल्यू स्टील के निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन) जयंत आचार्य ने कहा, 'फिर से स्टॉकिंग और मांग शुरू होने से उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं।'

अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि में लॉन्ग उत्पादों की उत्पादक जैसे नवीन जिंदल की अगुआई वाली जिंदल स्टील और सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के उत्पादन के आंकड़े मजबूत रहे थे, जो इस बात का संकेत है कि बुनियादी ढांचा में मांग बढ़ रही है।

जेएसपीएल की बिक्री दिसंबर तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 30 फीसदी बढ़कर 16.6 लाख टन रही। शर्मा ने कहा, 'हम वित्त वर्ष 2020 में करीब 70 लाख टन का उत्पादन कर 65 लाख टन के खुद के अनुमान से आगे निकल सकते हैं।'

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अयस्क की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद घरेलू लौह अयस्क की मांग में इजाफा हुआ है। घरेलू लौह अयस्क के दाम करीब 65 डॉलर प्रति टन हैं, जबकि आयातित अयस्क के दाम 85 से 90 डॉलर प्रति टन हैं। ओडिशा के खनिकों ने लौह अयस्क की कीमतें करीब 10 फीसदी बढ़ाई हैं, जबकि राज्य में आपूर्ति अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल इस्पात विनिर्माता चालू वित्त वर्ष के अंत में कई खदानों की लीज की अवधि खत्म होने के कारण आपूर्ति में अवरोध पैदा होने की आशंका के चलते अयस्क का स्टॉक कर रहे हैं।

इस्पात बनाने में लौह अयस्क और कोकिंग कोल दो अहम कच्चे माल हैं। केयर रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत का लौह अयस्क आयात 2019 में अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में 2018 की इसी अवधि के मुकाबले 90 फीसदी घटा है। वर्ष 2018 में अप्रैल से अक्टूबर तक अयस्क के आयात में 172 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

यह पिछले सात साल में सबसे कम आयात है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आलोच्य अवधि में वैश्विक लौह अयस्क की कीमतें ऊंची थीं। इस वजह से घरेलू इस्पात उत्पादकों ने महंगे आयात के बजाय घरेलू स्तर पर ही खरीद का विकल्प चुना। उद्योग के प्रतिनिधियों का अनुमान है कि अगले तीन महीनों में अयस्क की कीमतें 10 से 15 फीसदी और बढ़ेंगी क्योंकि लौह अयस्क की घरेलू और आयातित कीमतों में अंतर बहुत अधिक है।

आचार्य ने कहा, 'इस समय हम अपनी खदानों और स्थानीय बाजार से अयस्क ले रहे हैं। हमने आयातित अयस्क पर निर्भरता घटा दी है।' इस बीच सेल ने दिसंबर 2019 में अब तक की सबसे अधिक बिक्री 16.8 लाख टन की है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 47 फीसदी अधिक है। कंपनी ने नवंबर में भी सालाना आधार पर बिक्री में 36 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की थी।

टाटा स्टील, सज्जन जिंदल की अगुआई वाली जेएसडब्ल्यू स्टील और सरकारी कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में शामिल हैं।

पिछले दो सप्ताह के दौरान आईसीईएक्स पर लंबे इस्पात उत्पादों की कीमतें (एक्स-गाजियाबाद) 9 फीसदी बढ़कर 31,800 रुपये प्रति टन पर पहुंच गई हैं। इस्पात उत्पादों के सबसे बड़े द्वितीयक बाजार गोविंदगढ़ मंडी में हाजिर कीमतें भी इस बात का संकेत देती हैं कि द्वितीयक बाजार के उद्यमी भी कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं।

कमजोर घरेलू मांग के कारण चालू वित्त वर्ष से भारत के इस्पात निर्यात के लिए स्थितियां बदल गई हैं। कंपनियों ने कहा कि वे निर्यात जारी रखेंगी, लेकिन घरेलू बिक्री को तरजीह देंगी।

बीएसई 500 स्टील कंपनी (आंकड़े 2 जनवरी 2020 तक)

कंपनियां	रुपये	अंतर (%)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	47.3	10.1
जिंदल स्टील ऐंड पावर	173.4	4.3
मिश्र धातु निगम	161.7	4.1
टाटा मेटालिक्स	645.2	3.8
टाटा स्टील	485.0	3.7
महाराष्ट्र सीमलेस	395.2	3.2
जेएसडब्ल्यू स्टील	276.5	3.1
रत्नमणि मेटल्स ऐंड ट्यूब्स	1099.7	2.9
जिंदल स्टेनलेस हिसार	80.5	2.5
जिंदल स्टेनलेस	39.5	1.2
एपीएल अपोलो ट्यूब्स	1898.7	0.3
वेलस्पन कॉर्प	146.3	-0.4
जिंदल सॉ	85.0	-0.4

स्रोत- एक्सचेंज, संकलन- बीएस रिसर्च

चीनी मिलों ने किए 25 लाख टन निर्यात के अनुबंध

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 2 जनवरी

मौजूदा पेराई सत्र 2019-20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 तक घरेलू चीनी उत्पादन 30 प्रतिशत गिरकर 78 लाख टन रहने के बावजूद मिलें अब तक 25 लाख टन चीनी निर्यात के अनुबंध कर चुकी हैं। पिछले साल इस अवधि में 1.12 टन चीनी उत्पादन हुआ था। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने आज कहा कि मिलों ने अपनी अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा (एमएईक्यू) की तुलना में 25 लाख टन चीनी निर्यात के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

चीनी उद्योग

दरअसल केंद्र सरकार अक्टूबर-दिसंबर 2019 तिमाही के दौरान एमएईक्यू की तुलना में मिलों द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात की समीक्षा कर रही हैं और जैसा कि पहले ही इस नीति में घोषित किया जा चुका है, वह निर्यात न की जा सकी एमएईक्यू की मात्रा उन मिलों को फिर से आवंटित कर रही है, जो पहले ही निर्यात कर चुकी हैं और अपने एमएईक्यू से अधिक कोटा लेना चाहती हैं। इच्छुक मिलों को एमएईक्यू या अतिरिक्त कोटे के इस आवंटन से 2019-20 के दौरान एमएईक्यू का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बीच इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि हालांकि चीनी उद्योग के लिए निर्यात की स्थिति अब तक सकारात्मक रही है, लेकिन फिर भी आगे चलकर इसके लिए पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर वैश्विक चीनी बाजार के हालात अनुकूल रहते हैं, तो इस सत्र में भारतीय चीनी निर्यात 50 टन तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय चीनी के प्रमुख विदेशी गंतव्य ईरान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देश आदि हैं।

वर्तमान में देश भर में 437 मिलें सक्रिय हैं जो लगभग 78 लाख टन चीनी उत्पादन कर रही हैं, जबकि पेराई सत्र 2018-19 के दौरान 507 मिलें 1.12 करोड़ टन उत्पादन कर रही थीं। इस तरह चीनी उत्पादन में लगभग 34 लाख टन कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चुनाव के अलावा भारी बारिश और बाढ़ के बाद गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जलभराव के कारण पेराई की शुरुआत में बहुत अधिक देर हुई है। महाराष्ट्र में 137 मिलों ने 16.5 लाख टन चीनी उत्पादन किया है, जबकि पिछले साल 187 इकाइयों ने 44.5 लाख टन चीनी उत्पादन किया था। चीनी प्राप्ति में भी 10 से 10.5 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, हालांकि आने वाले सप्ताहों में इसमें इजाफा होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक 119 मिलों ने 33 लाख टन चीनी उत्पादन किया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 117 इकाइयों ने 31 लाख टन चीनी उत्पादन किया था। उम्मीद है कि वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश 1.2 करोड़ टन या देश के अनुमानित चीनी उत्पादन के 45 प्रतिशत भाग का उत्पादन करेगा। इस बीच देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटक में 63 मिलों ने 16.3 लाख टन चीनी उत्पादन किया है, जबकि पिछले सत्र में 65 इकाइयों ने 21 लाख टन उत्पादन किया था।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 31	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,800.00	6.1	1,961.50	-1.8
Copper	6,156.00	9.4	6,501.10	8
Nickel	14,000.00	-20.8	14,711.50	-17.7
Lead	1,923.50	-7.4	2,199.70	4.9
Tin	16,850.00	3.4	17,723.90	2.4
Zinc	2,293.00	-1	2,578.00	-2
Gold ($/ounce)	1,528.3*	1.9	1,702.10	4.5
Silver ($/ounce)	18.1*	3	20.2	4.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	66.5*	15.2	67.1	14.4
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-3.2	2.2	-5
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	193	14.3	312.4	6.2
Maize	188.6*	4.5	331.8	10.1
Sugar	359.6*	4.8	485.8	-1.3
Palm oil	777.5	49.5	1,222.50	43.9
Rubber	1,632.9*	15.1	1,835.40	5.4
Coffee Robusta	1,354.0*	3.8	1,863.50	-5.4
Cotton	1,531.10	15.3	1,617.90	-0.1

* As on Jan 02, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	44.2	17842
Oil and Oilseeds	359.4	57726
Spices	0.6	12
Metal(Dec 31)		
Metal- non ferrous	4042.9	47733
Metal- precious	10689.8	410
Oil and gas(Dec 31)		
Gas	2505.8	51768
Oil	15833.4	2576

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	233.1	116451
Grains	197.4	108015
Oil and Oilseeds	1289.2	564115
Others	117.2	72275
Pulses	118.8	43040
Spices	108.5	30147

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Aluminium (Dec 31)	141.3	3.4
Lead Mini (Dec 31)	154.7	3.2
Cardamom (Jan 15)	3971.3	3.0
Copper (Dec 31)	453.3	2.7
Zinc Mini (Dec 31)	183.4	2.5
Aluminium Mini (Dec 31)	141.3	2.4
Losers (* % Change)		
Nickel (Dec 31)	1054.1	-2.3
Natural Gas (Jan 28)	155.5	-1.5
Mentha Oil (Jan 31)	1293.5	-0.4
Crude Oil (Jan 17)	4386.0	-0.3
Silver (Mar 05)	46711.0	-0.3
Silver Mini (Feb 28)	46731.0	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6714.0	1.7
Barley Jaipur (Apr 20)	1720.0	1.3
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4216.0	0.6
Bajra (Jan 20)	2047.0	0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1131.0	0.5
Chana-Bikaner (Jan 20)	4534.0	0.5
Losers (* % Change)		
Soyabean Indore (Jan 20)	4388.0	-1.5
Coriander-Kota (Jan 20)	6948.0	-1.4
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4647.0	-1.2
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7666.0	-0.9
Guar Seed 10 (Jan 20)	4210.0	-0.5
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	942.2	-0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3971.3	9.3
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19630.0	3.6
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46728.0	1.0
Silver Ahm (Mar 05)	46711.0	1.0
Nickel Mumbai (Dec 31)	1054.1	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1293.5	-8.6
Copper Mum (Dec 31)	453.3	-1.6
Aluminium Mum (Dec 31)	141.3	-1.5
Alumini-Mumbai (Dec 31)	141.3	-1.5
Lead Mum (Dec 31)	154.7	-0.5
Lead Min Mumbai (Dec 31)	154.7	-0.5

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6714.0	7.0
29 mm Cotton-Rajkot (Jan 20)	18940.0	0.3
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2047.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Soy Bean Indore (Jan 20)	4388.0	-3.9
Moong-Merta City (Jan 20)	7396.0	-2.6
Barley Jaipur (Jan 20)	2139.0	-2.5
Coriander-Kota (Jan 20)	6948.0	-2.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16035.0	-1.3
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3210.0	-1.2
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7666.0	-1.1
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	825.5	-0.9

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals		...Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	104	(104)
Aluminium ingots /kg	140	(140)
Brass sheet cutting /kg	328	(328)
Brass utensil scraps/kg	312	(310)
Copper heavy scrap /kg	431	(431)
Copper utensil scraps/kg	402	(404)
Copper wire bar /kg	464	(464)
Lead ingots /kg	157	(157)
Nickel Cathodes /kg	1050	(1050)
Tin slabs /kg	1265	(1280)
Zinc slabs /kg	184	(183)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton		...Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10320	(10320)
DCH - 32 /Qtl	11248	(11248)
Jaydhar /Qtl	9926	(9983)
Shankar- 6 /Qtl	11051	(11051)

Source:Cotton Association of India

Oil		...Mumbai
Castor FSG /10kg	895	(890)
Castor Comm /10kg	885	(880)
Ricebran oil/10kg	820	(-)
Groundnut oil /10kg	1180	(1180)
Linseed oil /10kg	1000	(-)
Karanji /10kg	800	(-)
Palm oil /10kg	878	(860)
Sunflower exp ref /10kg	940	(935)
Sunflower oil exp /10kg	895	(895)
Soyabean ref / 10kg	935	(930)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar		...Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3352-3582	(3382-3592)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		...
NYSE Crude	61.23	(61.06)
Brent Crude (UK)	66.7	(66.31)
Brent Crude (WTI)	61.06	(61.06)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.17	(2.19)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	304.02	(290.12)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold		...Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	39058	(38962)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	39215	(39119)
Silver.999/ kg	46340	(46145)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18843.75	18883.60
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.50	143.35
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2050.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	2041.95	2042.25
Barley Jaipur (N)	1 Q	2170.20	2194.05
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4301.65	4302.50
Castor Seed-Kadi (N)	X	4250.00	4250.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4413.00	4448.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4650.00	4666.20
Chana-Akola (N)	X	4475.00	4512.50
Coriander-Gondal (N)	X	6753.00	6728.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	7000.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	7084.35	7106.50
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2173.15	2176.25
Cotton-Kadi (N)	1 B	18835.75	18883.60
CPO-Kandla (M)	10 K	817.30	811.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	842.40	833.40
Gold Ahm (M)	10 G	39076.00	39068.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	31386.00	31380.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3920.00	3917.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7797.50	7754.25
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4143.25	4146.90
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1278.35	1250.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17000.00	16950.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16425.00	16243.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1050.85	1055.65
Kapas-Rajkot (N)	X	1056.35	1056.90
Lead Mum (M)	1 K	155.40	155.50
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2034.40	2040.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2460.10	2436.35
Maize-Erode (N)	X	2095.55	2082.20
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2255.00	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	1996.00	2000.20
Moong-Merta City (N)	1 Q	7560.00	7593.75
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4887.65	4861.90
Nickel Mumbai (M)	1 K	1055.50	1051.70
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3150.00	3250.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	35000.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2110.00	2100.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	867.50	872.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	941.60	942.70
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	936.25	942.60
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	960.00	959.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46595.00	46257.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4595.00	4567.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4507.15	4472.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4595.50	4582.90
Soy Bean-Akola (N)	X	4542.00	4523.00
Soymeal Indore (N)	1 T	37060.00	36525.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3305.00	3265.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3428.55	3371.45
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3261.65	3265.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3504.75	3457.15
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3335.00	3310.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3108.35	3105.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6250.00	6273.90
Wheat Delhi (N)	1 Q	2340.00	2353.35
Wheat Kota (N)	1 Q	2217.50	2248.90
Wheat New Indore (N)	1 Q	2275.00	2300.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2160.00	2185.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2290.00	2310.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5900.00	5750.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	183.45	184.00

* as on Jan 01, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

बुलियन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के सामने प्रबंधन और सुरक्षा।
एमसीएक्स पर हेज करें।
MCX METAL & ENERGY Trade with Trust
www.mcxindia.com

DAY SESSION

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19630, 19650, 19590, 19630	2887	439	14775
Feb 28	19890, 19890, 19850, 19880	706	117	2054
Mar 31	20150, 20160, 20150, 20150	13	3	89
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2165, 2198, 2158, 2167	42450	3152	44960
Feb 20	2186, 2218, 2180, 2187	45590	3273	59340
Mar 20	2221, 2238, 2202, 2209	1530	136	6490
Apr 20	2245, 2259, 2230, 2249	310	24	1240
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1126, 1136.5, 1126, 1129	448	76	908
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1128, 1136.5, 1126.5, 1131	1612	894	4421
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2035, 2055, 2035, 2047	180	14	170
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1715, 1720, 1715, 1720	140	8	1090
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4230, 4248, 4196, 4210	22285	2595	50990
Feb 20	4280, 4298, 4244, 4260	23855	2795	54310
Mar 20	4310, 4326, 4300, 4300	155	20	455
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4210, 4238, 4190, 4216	4440	328	21405
Feb 20	4236, 4260, 4210, 4240	3250	283	15675
Mar 20	4194, 4238, 4170, 4218	315	58	6905
Apr 20	4200, 4238, 4200, 4226	170	32	1905
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	810.5, 817.8, 804.1, 814.6	34190	2403	40280
Feb 28	810, 819, 805.8, 815.4	8250	697	16420
Mar 31	809.3, 814, 803.5, 810.6	420	40	770
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1303, 1303.6, 1291.7, 1293.5	84.24	199	244.8
Feb 28	1306.8, 1306.9, 1290, 1304.5	5.4	15	10.08
May 29	1280, 1280, 1280, 1280	0.36	1	1.08
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4700, 4716, 4634, 4647	13520	1176	16140
Feb 20	4706, 4729, 4641, 4654	12950	1054	9110
Apr 20	4619, 4629, 4544, 4554	5900	499	11910
May 20	4612, 4630, 4566, 4600	180	17	780
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	944.2, 947.4, 935.4, 942.2	24350	2701	33145
Feb 20	941, 946.2, 933.2, 941.8	31245	3099	56170
Mar 20	933.6, 942.2, 929, 935.4	5435	503	23000
Apr 20	926.6, 938.4, 926.4, 932.8	610	72	1900
May 20	919.2, 923.8, 919.2, 923.8	30	3	20
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4452, 4480, 4362, 4388	42110	5522	97250
Feb 20	4480, 4506, 4360, 4404	63565	7345	172865
Mar 20	4506, 4528, 4402, 4426	8485	1120	82090
Apr 20	4550, 4556, 4438, 4458	3240	395	12990
May 20	4500, 4528, 4500, 4502	370	34	855
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7740, 7767, 7650, 7666	6055	909	20720
Feb 20	7832, 7865, 7750, 7763	8220	1158	49425
Mar 20	7925, 7934, 7851, 7896	810	66	2130
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4516, 4548, 4516, 4534	17370	1341	28280
Mar 20	4461, 4497, 4461, 4473	8820	638	14190
Apr 20	4480, 4490, 4480, 4490	80	6	460
Wheat-Kota NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2200, 2230, 2200, 2230	40	2	40
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3971.3, 3971.3, 3971.3, 3971.3	0.1	1	6.5
Feb 14	3785, 3907.7, 3750, 3826.8	1.6	16	5.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	7040, 7142, 6864, 6948	5700	530	7580
Apr 20	7548, 7548, 7303, 7344	4010	364	8000
May 20	7372, 7450, 7340, 7375	90	9	120
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16000, 16115, 15945, 16035	405	124	1557
Mar 20	15630, 15660, 15555, 15600	291	96	1179
Apr 20	15385, 15385, 15310, 15355	120	40	411
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6628, 6820, 6608, 6714	2750	502	6800
Apr 20	6536, 6710, 6510, 6608	1000	182	4450
May 20	6600, 6662, 6600, 6620	20	4	50
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	141.9, 141.9,

युवा वैज्ञानिकों के हाथ कमान!

डीआरडीओ की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में 35 साल से कम उम्र के लोगों की नियुक्ति

अजय शुक्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंगलूरु में पांच नई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इन प्रयोगशालाओं में केवल 35 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाएगा, जो सैन्य हथियारों के लिए आधुनिक और भविष्योन्मुखी तकनीक विकसित करेंगे। मोदी ने 2014 का चुनाव जीतने के तीन महीने बाद प्रस्ताव रखा था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को अपने युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन एवं मदद दे। इसके लिए कम से कम पांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए, जहां निदेशक समेत हर कोई 35 साल से कम उम्र का हो।

मोदी ने कहा, 'हमें भारत में ऐसी प्रयोगशालाओं की जरूरत है, जिनमें नई प्रतिभाओं का इस्तेमाल हो और इनमें केवल 35 साल से कम उम्र के लोगों को नियुक्त किया जाए। इन युवा वैज्ञानिकों को फैसले लेने की पूरे अधिकार दिए जाएं।'

उनके इस प्रस्ताव के चलते ही पांच तथाकथित डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं (डीवाईएसएल) बेंगलूरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित की गई हैं। डीआरडीओ ने गुरुवार को कहा, 'प्रत्येक प्रयोगशाला भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण उन्नत तकनीक पर काम कर रही है।'

डीआरडीओ ने घोषणा की, 'तेजी से विकसित होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान बेंगलूरु में होगा। क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान आईआईटी मुंबई में होगा। वहीं भविष्य कॉग्निटिव तकनीकों पर निर्भर है और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चेन्नई में प्रयोगशाला स्थापित की गई है। एसमेट्रिक तकनीक का नया और भविष्योन्मुखी क्षेत्र युद्धों का तरीका बदल देगा। इस तकनीक में अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला कोलकाता में जाधवपुर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित होगी। स्मार्ट मैटेरियल और उनके उपयोग के क्षेत्र में शोध हैदराबाद में होगा।'

प्रधानमंत्री डीआरडीओ की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए

लोकेशन	तकनीकी दक्षता
डीआरडीओ बेंगलूरु (एआई)	आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस
आईआईटी बंबई	क्वांटम टेक्नोलॉजी
आईआईटी चेन्नई	कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी
जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी
आईआईटी हैदराबाद	स्मार्ट मैटेरियल्स

भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन की अध्यक्षता वाली समिति ने इन प्रयोगशालाओं के निदेशकों का चयन किया है। डीआरडीओ ने कहा, 'निदेशकों को डीआरडीओ की किसी प्रयोगशाला के निदेशक के समान ही वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।' हालांकि पांच डीवाईएसएल युवाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, लेकिन डीआरडीओ की मौजूदा 52 प्रयोगशालाएं पहले ही 21वीं सदी के विषयों जैसे साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक हथियार और अंडरवाटर सिस्टम में अनुसंधान के लिए बड़ी तादाद में युवा वैज्ञानिकों का इस्तेमाल कर रही हैं।

मोदी ने वैज्ञानिकों और नए प्रयोग करने वालों से अपना दायरा व्यापक करने को कहा है क्योंकि सरकार उनके साथ है। डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में उन्होंने वैज्ञानिकों को आश्वस्त किया कि सरकार देश के वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के साथ है। उन्होंने कहा, 'आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ ही दुनिया की रणनीतिक गतिशीलता परिभाषित होगी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में इंटेलीजेंट मशीनों की भी आने वाले दिनों में भूमिका होगी। ऐसी स्थिति में भारत पिछड़ नहीं सकता है।'

उनका कहना था कि नागरिकों, सीमाओं और हितों की सुरक्षा के लिए भविष्य की तकनीक और नए प्रयोग में निवेश अहम है।

डेटा संरक्षण विधेयक से चिंतित दिख रहे फॉरेंसिक ऑडिटर

फॉरेंसिक ऑडिटर को जांच के लिए कर्मियों की निजी जानकारी लेनी होती है लेकिन निजी डेटा संरक्षण विधेयक इस पर प्रतिबंध लगाता है

रुचिका चित्रवंशी और नेहा अलावधी

डेटा संरक्षण कानून ने फॉरेंसिक ऑडिटर के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। वे संबंधित कानून में अपने लिए विशेष छूट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बैंक जानकरियां, ई-मेल, चिकित्सा बीमा जैसी कई निजी जानकारियों को देखना होता है।

एक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कंपनी के रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित कंपनी की हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और उसके कुछ कर्मचारियों के निजी डेटा तक पहुंच बनाने की आवश्यकता होती है। हार्ड ड्राइव के डेटा में आधिकारिक एवं व्यक्तिगत, दोनों तरह की जानकारी शामिल होती है और फॉरेंसिक ऑडिटर को इन सभी जानकारियों की आवश्यकता होती है।

संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हुआ निजी डेटा संरक्षण विधेयक में कहा गया है, 'किसी डेटा के प्रसंस्करण के समय उस डेटा से जुड़े व्यक्ति की सहमति के बिना निजी डेटा का प्रसंस्करण नहीं किया जा सकता।' इसमें कहा गया है कि स्पष्ट तथा कानूनी जरूरतों के लिए चयनित व्यक्ति के अलावा कोई अन्य निजी डेटा का प्रसंस्करण नहीं कर सकता और डेटा प्रसंस्करण के लिए संबंधित व्यक्ति से सहमति लेने के प्रमाण साबित करने की जिम्मेदारी प्रसंस्करण करने वाले व्यक्ति की होगी।

हालांकि इस तरह के डेटा का प्रसंस्करण करते समय नियोक्ता को व्यक्ति से औपचारिक सहमति लेने की आवश्यकता होगी जिससे कर्मी की डिजिटल आंकड़े तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक इमेजिंग आदि काम किए जा सकें।

ग्रांट थॉर्नटन में प्रमुख (फॉरेंसिक) समीर परांजपे कहते हैं, 'एक औपचारिक सहमति गोपनीयता की प्रकृति को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया लगता है कि विधेयक में व्यक्तियों को भी सहमति वापस लेने का भी अधिकार है जो किसी भी कारोबारी जांच को बाधित करने की क्षमता रखता है।'

फॉरेंसिक ऑडिटरों ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित कानून से अनेक समस्याएं पैदा होंगी। उदाहरण के लिए, फंड ट्रेल की जांच करना के लिए ऑडिटर को किसी व्यक्ति के निजी बैंक खाते की जानकारी लेनी होंगी। डेलॉइट इंडिया में पार्टनर जयंत सरन ने कहा, 'इससे फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने वाली कंपनियों के नैतिक हित प्रभावित होंगे। विधेयक में कुछ क्षेत्रों को अपवाद के तौर पर रखने की आवश्यकता है।'

इसी तरह, देश से बाहर की स्थिति में, जहां मुद्रा को बदलकर किसी दूसरे देश भेज दिया गया हो, इससे संबंधित मामले में फॉरेंसिक ऑडिटर के सामने डेटा स्थानीयकरण के नियम एक समस्या खड़ी करेंगे।

सरन कहते हैं, 'डेटा एनालिटिक्स एवं प्रक्रिया मूल्यांकन में बहुत सी दूसरी जानकारी भी सामने आएगी जैसे वेंडर संबंधी जानकारी, यात्रा खर्च, भुगतान आदि।'

हालांकि विधेयक में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा प्रसंस्करण करने संबंधी प्रावधान हैं लेकिन इसमें उल्लिखित परिस्थिति में किसी फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल नहीं किया गया है।

कानूनी सलाहकार फर्म निशीथ देसाई एसोसिएट्स में पार्टनर प्रतिभा जैन कहती हैं, 'विधेयक में किए गए प्रावधान काफी व्यापक हैं। हमें विधेयक के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए नीति-नियम निर्माण का इंतजार करना चाहिए। इन प्रावधानों से न सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट, बल्कि नियामकीय प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है।'

हालांकि फॉरेंसिक ऑडिटर आम प्रक्रिया में निजी डेटा अलग रखते हैं लेकिन अगर किसी विशेष तथ्य की जांच या कीवर्ड के दौरान निजी डेटा की जरूरत पड़ती है तो उन्हें संबंधित मामले में गहराई में जाने के लिए इस डेटा की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, अगर किसी व्यक्ति को सहमति वापस लेने का अधिकार होगा तो इससे भी फॉरेंसिक जांच प्रभावित होगी।

भले ही विधेयक का अधिकांश ध्यान आईटी कंपनियों पर केंद्रित रहा है लेकिन यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जो डेटा एकत्र कर रही हैं। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कई और मुद्दे सामने आएंगे क्योंकि कई उद्योगों को निजी डेटा संरक्षण विधेयक से प्रभावित होने की अहसास होगा।

इमेजिंगः अजय मोहंती

कैसे हैं प्रावधान

- विधेयक के अनुसार, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता निजी डेटा का प्रसंस्करण
- सहमति लेने के प्रमाण साबित करने की जिम्मेदारी प्रसंस्करण करने वाले व्यक्ति की
- ऑडिटर्स को जांच के समय बैंक, ई-मेल, चिकित्सा बीमा जैसी कई निजी जानकारियां देखना जरूरी
- सहमति वापस लेने के अधिकार से भी प्रभावित होगी फॉरेंसिक जांच
- संबंधित प्रावधानों से नियामकीय प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ने की संभावना
- दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया है विधेयक

'पाक के जुल्म के खिलाफ भी करें प्रदर्शन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर गुरुवार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जारी प्रदर्शन संसद के खिलाफ है। मोदी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे पाकिस्तान में पिछले 70 साल से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और उनका समर्थन करना देश की संस्कृति और राष्ट्रीय दायित्व है जिन्होंने भारत में शरण मांगी है। उन्होंने कहा, 'जो भारत की संसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरूरत पाकिस्तान के कृत्यों को विश्व मंच पर उजागर करने की है। यदि आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के पिछले 70 वर्षों के कृत्यों के खिलाफ प्रदर्शन करें और अपनी आवाज उठाएं।'

मोदी ने कर्नाटक के टुमकुरू स्थित सिद्धगंगा मठ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगी और उनके द्वारा निर्मित तंत्र भारतीय संसद के खिलाफ खड़े हैं। भाजपा के प्रति उनके मन में जिस तरह की नफरत है वैसी ही आवाज इन दिनों देश की संसद के खिलाफ भी सुनी जा सकती है। इन लोगों ने देश की संसद के खिलाफ विरोध शुरू किया है। ये लोग दलितों के खिलाफ, दबे कुचलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो पाकिस्तान से शरण मांगने के लिए आए हैं।' मोदी ने कहा कि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना था और भारत का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था।

> नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के शोषण पर कभी बात नहीं करता है

उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय से पाकिस्तान में अन्य धर्म के लोगों ने अत्याचार का सामना किया। उन्होंने कहा, 'चाहे हिंदू हो, सिख, ईसाई या जैन हों समय के साथ उनके खिलाफ अत्याचार बढ़े। ऐसे हजारों लोगों को घर द्वार छोड़कर शरणार्थी के तौर पर भारत आना पड़ा।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुओं, सिखों, जैनों के खिलाफ अत्याचार किए लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते बल्कि इसके बजाय वे उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपना धर्म बचाने और अपनी बहनों और बेटियों का आत्मसम्मान बचाने के लिए भारत में शरण ली।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करके जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन से आतंकवाद को लेकर भय और अनिश्चितता समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की एक नई शुरुआत हुई है।

कानूनी वैधता नहीं

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग करने वाले केरल विधानसभा में पारित प्रस्ताव की कोई संवैधानिक या कानूनी वैधता नहीं है। खान ने पत्रकारों से कहा कि राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि नागरिकता का विषय केंद्र सरकार के अधीन आता है।

सूखे खेत और भूमिगत जल का नहीं कोई आसरा

हरियाणा के गांवों में भूमिगत जल बनाए रखने की कोशिश हो रही है पर राजस्थान के किसानों के पास न तो पानी है और न उम्मीद

ज्योति मुकुल

राजस्थान और हरियाणा के कई हिस्सों में महिलाओं का बाहर निकलकर बात करना असामान्य है। ऐसे में जयपुर जिले की चौमू तहसील के उदयपुरिया गांव में प्रेम देवी जब बोलना शुरू करती हैं तब वह इस असमंजस में होती हैं कि उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए या या खड़े रहकर।

उनके आंगन के बाहर एक पेड़ पर लगे पपीतों को प्लास्टिक से लपेटा हुआ है। ये दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन अभी पके नहीं है। वह बताती हैं कि कैसे उनकी आधा हेक्टेयर से भी कम जमीन पर दो बोरवेल थे जिनसे छह साल पहले ही पानी निकलना बंद हो गया। उनका परिवार बाजरा उगाने के लिए अब बारिश की सिंचाई पर ही पूरी तरह निर्भर है जिसे लोग घर में खाते भी हैं और बकरी के लिए चारे का इंतजाम भी हो जाता है। उनका बेटा अपनी आजीविका चलाने के लिए एक निर्माण परियोजना में काम करता है।

उनकी कई शिकायतों में ग्रिड बिजली की शिकायत भी है। उनके परिवार को बिजली के बिल में 833 रुपये की सब्सिडी मिलती है लेकिन अब नियम में बदलाव की वजह से बैंक खाते में नकदी हस्तांतरण होता है। वह कहती हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिलता है और अधिकारी कहते हैं कि शायद उनका बैंक खाता नहीं जुड़ा होगा।

जयपुर और आगरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के भरणी गांव में मुरली धर के सूखे खेत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। उनके परिवार में 12 सदस्य हैं और उनके बेटे मजदूरी करते हैं जिससे उनका घर चलता है। वह बारिश के मौसम में ही बाजरा और एक किस्म की तिलहन तारामिरा उगाते हैं जो देश के उत्तरी पश्चिमी सूखे क्षेत्र में उगाई जाती है।

सूरज, पानी और मिट्टी
भाग-3

तारामिरा सरसों की फसल की तरह ही होता है जिसे परंपरागत तौर पर राजस्थान और हरियाणा में उगाया जाता है। झुंझुनू जिले में बागवानी विभाग के सहायक निदेशक धर्मवीर डूडी कहते हैं कि गेहूं की तुलना में इस क्षेत्र के लिए तिलहन अच्छी फसल है। वह कहते हैं, 'अगर गेहूं से प्रति क्विंटल 2,000 रुपये मिलते हैं तब सरसों से करीब 4,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा गेहूं में ज्यादा खाद देने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए कम से कम छह से सात बार सिंचाई करनी होती है। सरसों में केवल तीन बार सिंचाई करनी पड़ती है और खाद भी कम लगता है। इसके अलावा सरसों के पत्ते से सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं जो मिट्टी की सेहत के लिए अच्छे होते हैं।'

झुंझुनू जिले से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक खेतों के बीच कई खेजड़ी के पेड़ नजर आते हैं। इन पंरपरागत पेड़ों से मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है और इसे क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है। डूडी का कहना है, 'आपको राजस्थान में ऐसे पेड़ खूब देखने को मिलेंगे। जब आप सीमा पार कर हरियाणा की तरफ जाते हैं तब आपको ऐसा नहीं दिखेगा।'

यह सड़क हरियाणा में नारनौल की तरफ बढ़ती है जहां छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की चर्चा है। भैंसावता खुर्द गांव के काशी राम इस बात को लेकर हैरानी जताते हैं कि इस सड़क से उनकी किस्मत बदलेगी या नहीं। उनके सूखे खेत से कोई आमदनी नहीं हो पाती। उनके परिवार को गांव के एक कुएं से पीने का पानी मिलता है और सिंचाई के लिए उन्हें बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुछ साल पहले उन्होंने मुर्गीपालन का काम किया था लेकिन यह चल नहीं पाया। वह कहते हैं, 'मैं मुर्गीपालन वाला शेड अब शादियों के लिए देता हूं।'

राजस्थान और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में पानी की दिक्कत है। ऐसे में राज्य सरकारों ने सौर संचालित पंप योजना के लिए सूक्ष्म सिंचाई को अनिवार्य बना दिया है। ऐसे में सिंचाई के लिए बिजली बिल शून्य हो जाता है लेकिन ज्यादा मात्रा में भूमिगत जल निकाले जाने का खतरा बना रहता है।

राजस्थान सरकार में निदेशक (बागवानी) वी श्रवण कुमार कहते हैं कि राज्य कई सौर जल पंप नियंत्रक को बढ़ावा देगा ताकि सिंचाई से इतर दूसरे कामों मसलन थ्रेशिंग और आटा चक्की आदि के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके। वह कहते हैं, 'सिंचाई के लिए एक कनेक्शन और दूसरे इस्तेमाल के लिए तीन की जरूरत होगी।' केंद्र की कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी में किसान, बिजली वितरण कंपनियों को अतिरिक्त बिजली बेचेंगे। इसका लक्ष्य भूमिगत जल के ज्यादा इस्तेमाल को रोकना है।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के देरोली अहीर गांव में एक दूसरी ही स्थिति नजर आती है जो सिंचाई वाली नहरों के नजदीक हैं। भूप सिंह कहते हैं, 'सूखी जमीन की समस्या को आंशिक रूप से बदल दिया गया है।' गांव की पंचायत ने एक हेक्टेयर जमीन तालाब और दो कुएं बनाने के लिए दिया है। बारिश के पानी के अलावा नारनौल नहर से निकलने वाला ज्यादा पानी इन जगहों पर जमा हो जाता है। सिंह अपने पुराने घर के बगल में नया घर बनाने में व्यस्त हैं क्योंकि उनके बेटे की शादी होने वाली है। वह कहते हैं, 'पांच किलोमीटर के दायरे में यह जीवनरेखा बन गई है।' हालांकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके नए घर की छाया की वजह से बगल में मौजूद सोलर पैनल का उत्पादन कम हो सकता है।

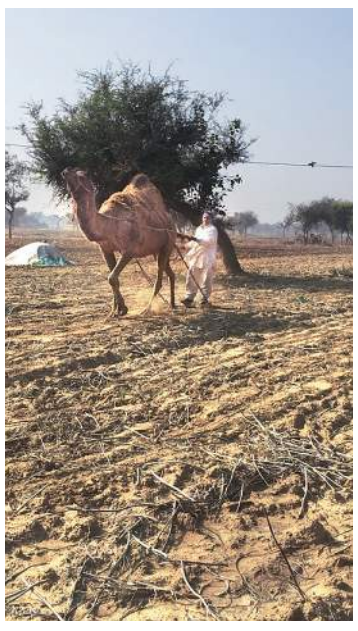

भैंसावता खुर्द के किसान काशी राम और उदयपुरिया गांव की प्रेम देवी खेती से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए

भूमिगत जल का दायरा

आंकड़े अरब क्यूबिक मीटर में*

	राजस्थान	हरियाणा
सालाना भूमिगत जल फिर से भरना	13.21	10.15
सालाना निकाले जाने योग्य भूमिगत जल संसाधन	11.99	9.13
सालाना भूमिगत जल संग्रह	16.77	12.50
भूमिगत जल निकालने का चरण (%)	140	137

* बिलियन क्यूबिक मीटर

राजस्थान

आकलन वाले कुल ब्लॉक 295

अत्यधिक इस्तेमाल	185
गंभीर	33
कम गंभीर	29
सुरक्षित	45
खारा	3

हरियाणा

आकलन वाले कुल ब्लॉक 128

अत्यधिक इस्तेमाल	78
गंभीर	3
कम गंभीर	21
सुरक्षित	26

स्रोतः भारत के गतिशील भूमिगत जल संसाधन का राष्ट्रीय संकलन, 2017, सीजीडब्ल्यूबी

6 करोड़ किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ पंजीकरण नहीं कराने वाले राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी राजनीति से किसानों को नुकसान हो रहा है। मोदी ने टुककुरू के एक कार्यक्रम में देश के छह करोड़ किसानों के खाते में 12 हजार करोड़ रुपये जमा करवाए।